एक्ज़िम बैंक
EXIM BANK
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

एक्ज़िमिअस निर्यात लाभ

सितंबर 2017
खंड XXXIII अंक III

इस अंक में

1 ब्रिक्स: भारतीय परिप्रेक्ष्य-मजबूत भागीदारी का निर्माण
4 भारतीय ऑटोमोबाइल और कलपुर्जा उद्योग: वर्तमान रुझान एवं संभावनाएं
5 कच्चा (क्रूड) तेल तथा पेट्रोलियम उत्पाद: हालिया रुझान एवं परिदृश्य
6 बिम्स टेक देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार
7 पर्यावरणीय वस्तुओं (ईजी) में व्यापार
8 भारत-म्यांमार व्यापार पर एक नजर
9 एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएं
10 तिमाही गतिविधियाँ
11 संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध
12 एक्ज़िम बैंक गतिविधियां
13 देशों का सूक्ष्मावलोकन
14 मुद्रा की प्रवृत्तियां
15 भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य
16 व्यापार और भागीदारी अवसर

भारतीय निर्यात-आयात बैंक का तिमाही प्रकाशन
www.eximbankindia.in

ब्रिक्स: भारतीय परिप्रेक्ष्य-मजबूत भागीदारी का निर्माण

ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नामों का संक्षिप्त रूप ही ब्रिक्स है। पिछले 10 वर्षों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में पांचवें से भी ज्यादा हिस्सा केवल ब्रिक्स देशों का है, और ब्रिक्स ने विश्व आर्थिक विकास में 50% से अधिक योगदान दिया है। ब्रिक्स देश विश्व के 43% जनसमूह का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्ष 2001 में जब दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल नहीं था तब, गोल्डमैन साक्स के जिम ओ'नील ने अपने एक पेपर 'बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स' में इसे पहली बार ब्रिक्स नाम दिया। इस पेपर में यह निष्कर्ष निकला कि अगले 10 वर्षों में, विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में ब्रिक देशों, विशेषकर चीन का प्रभाव बढ़ेगा और ब्रिक देशों में वित्तीय और मौद्रिक नीति के वैश्विक आर्थिक प्रभाव के विषय में महत्त्वपूर्ण मुद्दों को उठाया जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 61वें सत्र के सामान्य विचार-विमर्श से इतर चीन, ब्राजील, रूस और भारत के बीच ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक 2006 में हुई थी, जिसमें ब्रिक सहयोग हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया था। पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में येकतेरिनबर्ग, रूस में हुआ। तभी से शिखर सम्मेलन एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया। अब तक इसके 9 शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। दिसंबर 2010 में, चीन ने अपनी अध्यक्षता में सान्या (चीन) में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। ब्रिक में औपचारिक रूप से 5 देश शामिल हो गए और इसका संक्षिप्त नाम ब्रिक्स हो गया। एशिया, अफ्रीका और अमेरिका महाद्वीप से उभरती ये पाँच वैश्विक शक्तियां अपनी वैश्विक व्यस्तताओं को वृद्धिशील रूप से बढ़ाने और असंख्य क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने के लिए अपने आर्थिक बल का उपयोग कर रही हैं।

ब्रिक्स का वैश्विक व्यापार

वैश्विक जीडीपी में अपने बढ़ते हिस्से की तरह ही, ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं विश्व व्यापार के सशक्त विकास को गति प्रदान करने में भी सबसे आगे रही हैं। वैश्विक व्यापार (निर्यात और आयात सहित) में ब्रिक्स का हिस्सा वर्ष 2007 के 12.6% से बढ़कर वर्ष 2016 में 16.4% हो गया। इसी तरह ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं के वैश्विक निर्यात में वर्ष 2007 के 14.1% के स्थान पर वर्ष 2016 में 18.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

ब्रिक्स का कुल व्यापार वर्ष 2007 के 3.5 खरब यूएस डॉलर से बढ़कर वर्ष 2016 में 5.2 खरब यूएस डॉलर हो गया। पिछले दो वर्षों में, ब्रिक्स के कुल व्यापार में काफी गिरावट आई। वर्ष 2015 में सभी ब्रिक्स देशों के निर्यात में गिरावट आई। वर्ष 2016 में केवल दक्षिण अफ्रीका के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई।

[1]अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़े

चार्ट 1: सम्पूर्ण विश्व के साथ ब्रिक्स देशों का व्यापार (ट्रिलियन यूएस डॉलर)

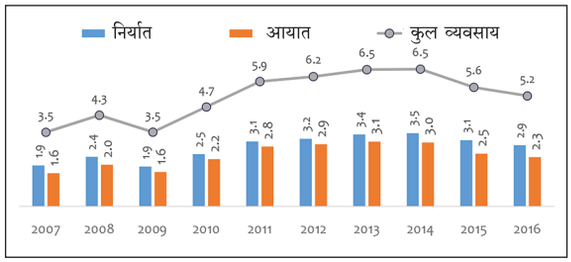

स्रोत: ट्रेडमैप, आईटीसी जेनेवा

चार्ट 2: विश्व निर्यात-आयात में ब्रिक्स का हिस्सा

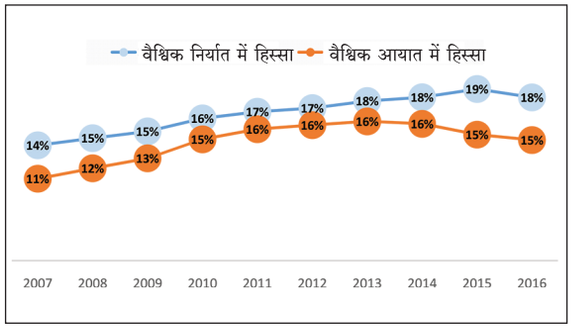

स्रोत: ट्रेडमैप, आईटीसी जेनेवा

ब्रिक्स के साथ भारत का व्यापार

पिछले दशकों में ब्रिक्स के साथ भारत का व्यापार 45.8 अरब यूएस डॉलर से बढ़कर 90.2 अरब यूएस डॉलर हो गया है। जब विश्व को भारत के निर्यात की तुलना में ब्रिक्स को भारतीय निर्यात वर्ष 2007 के 9.9% से गिरकर 2016 में 6.3% रह गया, तो उसी अवधि के दौरान आयात का हिस्सा 14.3% से बढ़कर 20.7% हो गया। परिणामस्वरूप, ब्रिक्स के साथ भारत का व्यापार घाटा वर्ष 2007 में 16.9 अरब यूएस डॉलर से बढ़कर वर्ष 2016 में 57.7 अरब यूएस डॉलर हो गया।

वर्ष 2016 में भारत द्वारा ब्रिक्स को निर्यात की गई प्रमुख वस्तुओं में खनिज ईंधन और तेल (9.3%); खनिज रसायन (8.3%); कपास (8.3%); अयस्क, धातु, भस्म (7.2%); तथा मशीनें और यांत्रिक उपकरण (6.1%) इत्यादि शामिल रहे। दूसरी ओर, वर्ष 2016 में ब्रिक्स से भारत द्वारा आयातित प्रमुख वस्तुओं में विद्युत मशीनरी एवं उपकरण (28.3%); मशीनरी और यांत्रिक उपकरण (14.9%); जैविक रसायन (7.8%); मोती एवं बहुमूल्य रत्न (5.8%); तथा लोहा और स्टील (5.8%) शामिल रहीं।

ब्रिक्स देशों में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार चीन है, जिसका हिस्सा लगभग 77% है। चीन के बाद दक्षिण अफ्रीका (9.1%), रूस (7.3%) और ब्राज़ील (6.6%) का स्थान है।

चार्ट 3: ब्रिक्स के साथ कुल व्यापार में हिस्सा

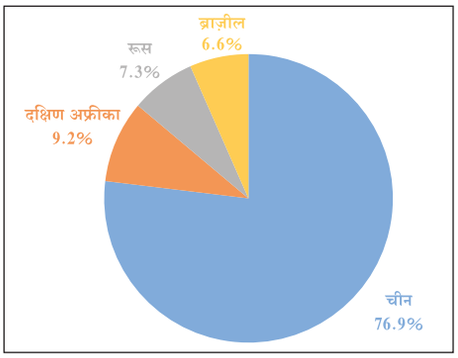

स्रोत: ट्रेडमैप, आईटीसी जेनेवा

नौवाँ ब्रिक्स सम्मेलन शियामेन, चीन में

इन दस वर्षों के दौरान, आरंभ से ही ब्रिक्स समूह ने अपने आधार को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं और विकास में सहयोग देने के लिए अब यह एक महत्त्वपूर्ण मंच के रूप में विकसित हो चुका है। वर्ष 2017 में चीन ने अधिकृत रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता प्राप्त करते हुए, नौवां ब्रिक्स सम्मेलन चीन में आयोजित किया। इसका विषय था ब्रिक्स: उज्ज्वल भविष्य के लिए मजबूत भागीदारी। सम्मेलन का उद्देश्य निम्न बिन्दुओं का निर्माण एवं व्यवस्था को और सुदृढ़ करना था:

- **ऐसी भागीदारी जो विश्व शांति का समर्थन करे।** ब्रिक्स देशों को सामान्य, व्यापक, सहकारी और स्थायी सुरक्षा का समर्थन करते हुए समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए तथा एक-दूसरे का समर्थन करना चाहिए। यह आवश्यक है कि अंतरराष्ट्रीय निष्पक्षता और न्याय को बनाए रखा जाए तथा विवादों के राजनीतिक समाधान वार्ता एवं समझौते द्वारा किए जाएं।
- **ऐसी भागीदारी जो सामान्य विकास को बढ़ावा देती हो।** ब्रिक्स देशों द्वारा व्यापक आर्थिक नीति को सहयोग दिया जाए। संरचनात्मक सुधार करते हुए विकास के नवीन मॉडल अपनाए जाएं तथा एक मुक्त विश्व अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए। विकास के झंडे को ऊंचा रखने, बाजार के अंतर-संबंधों को सुविधाजनक बनाने, आर्थिक समन्वय करने तथा ब्रिक्स देशों को आपस में आधारभूत संरचना द्वारा जोड़ने के लिए निरंतर गहन प्रयास किए जाएं।
- **ऐसी भागीदारी जो विभिन्न संस्कृतियों को आगे बढ़ाती हो।** ब्रिक्स देशों को लोगों में निकटता बढ़ाने के लिए बहु-आयामी मित्रवत आदान-प्रदानों और आपसी संपर्क का समर्थन करना चाहिए। ब्रिक्स समूह के लोगों के बीच आपसी समझ और पारम्परिक मित्रता को बढ़ावा दिया जाए, ताकि ब्रिक्स संघ व्यापक समर्थन प्राप्त कर सके।
- **ऐसी भागीदारी जो उन्नत वैश्विक आर्थिक प्रशासन को समर्पित हो।** ब्रिक्स देशों को वैश्विक आर्थिक प्रशासन में सुधार करते हुए उसे निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए ताकि इसमें उभरते बाजारों और विकासशील देशों का ऐतिहासिक ट्रेंड दिखे तथा इन देशों को अंतरराष्ट्रीय मामलों में ऊंचा स्वर और प्रतिनिधित्व दिया जाए।

शियामेन में हुई उद्घोषणाओं की विशेषताएँ

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई शियामेन उद्घोषणाओं पर सदस्यों के हस्ताक्षर कराए गए और इसका महत्त्व बताते हुए कहा गया कि एक संगोष्ठी के रूप में ब्रिक्स ने, सदस्यों के बीच आपसी आदर, समझ, समानता, समन्वय, निष्पक्षता, समावेश तथा परस्पर लाभकारी सहयोग को बढ़ावा दिया है। उन्होंने बार-बार शांति, सुरक्षा, विकास एवं सहयोग की इच्छा बनाए रखने की इच्छा को व्यक्त किया। इन बिन्दुओं पर सभी सदस्यों की सहमति के साथ सम्मेलन का समापन हुआ –

- उदार भागीदारी का प्रयास करना, ब्रिक्स तथा ब्रिक्स प्लस देशों ने उभरते बाज़ारों और विकासशील देशों के साथ उदार भागीदारी का प्रयास करने तथा कदम से कदम मिलाकर चलने एवं लचीला व्यवहार रखने के लक्ष्य को सहमति प्रदान की। ब्रिक्स प्लस (इसमें थाईलैंड, तजाकिस्तान, मिस्र, केन्या और मैक्सिको आते हैं) के संगठन सहित गैर-ब्रिक्स देशों के साथ वार्ता एवं सहयोग की पहल करने की भी सहमति दी।
- ब्रिक्स स्थानीय मुद्रा बांड बाज़ार- सदस्य देशों ने ब्रिक्स स्थानीय मुद्रा बांड बाज़ार के विकास को प्रोत्साहन देने सहित संयुक्त रूप से एक ब्रिक्स स्थानीय मुद्रा बांड निधि की स्थापना तथा वित्तीय बाजार एकीकरण को सुगम बनाने का भी संकल्प लिया। सदस्य देशों ने ब्रिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर नेटवर्क की स्थापना की संभावनाएं तलशते पर भी सहमति व्यक्त की।
- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास तथा नवीनीकरण- थिंग्स ऑफ इंटरनेट सहित बिग डाटा, डाटा विश्लेषण, क्लाउड कंप्यूटिंग, नैनोटेक्नोलॉजी वाली कृत्रिम बुद्धि, 5G जैसे क्षेत्रों में नवोन्मेषी पहलों के साथ उन्होंने सूचना एवं संचार तकनीक (आईसीटी) में संयुक्त अनुसंधान विकास और नवीनीकरण को बढ़ाने की भी सहमति दी।
- ऊर्जा में सहयोग- ब्रिक्स संगठन ने ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और प्रौद्योगिकियों के लिए खुले, लचीले और पारदर्शी बाजारों को बढ़ावा देने की सहमति दी। उन्होंने जीवाश्म ईंधन के सबसे प्रभावी उपयोग को प्रोत्साहन देने और गैस, जल तथा परमाणु ऊर्जा के व्यापक उपयोग के माध्यम से कम उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने तथा बेहतर ऊर्जा विकल्प और सतत विकास की दिशा में एक साथ काम करने के लिए भी सहमति प्रकट की।
- ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच- इसे भारत में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह प्राथमिक क्षेत्रों में वास्तविक नेटवर्क सहयोग को सुगम बनाएगा।
- लोगों में आपसी आदान-प्रदान - ब्रिक्स देशों के लोगों बीच आपसी समझ, मैत्री और सहयोग के विकास और वृद्धि के लिए इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

वार्षिक ब्रिक्स अर्थशास्त्र अनुसंधान पुरस्कार

वर्ष 2016 में ब्रिक्स फोरम की भारत द्वारा की गई अध्यक्षता में एक्ज़िम बैंक ने ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग व्यवस्था की अध्यक्षता की थी। इसी अध्यक्षता के दौरान एक्ज़िम बैंक द्वारा मार्च 2016 में ब्रिक्स आर्थिक शोध पुरस्कार की स्थापना की गई। पुरस्कार का उद्देश्य ब्रिक्स के सदस्य देशों से संबंधित समकालीन, प्रासंगिक, अर्थशास्त्र संबंधी विषयों पर शोध को बढ़ावा और प्रोत्साहन देना है। पुरस्कार में 15 लाख रुपए (लगभग 23000 यूएस डॉलर), एक पदक और प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

बीजिंग में चाइना डेवलपमेंट बैंक (सीडीबी) द्वारा आयोजित 7वें वार्षिक ब्रिक्स वित्तीय फोरम के दौरान भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) द्वारा दिए जाने वाले ब्रिक्स आर्थिक शोध पुरस्कार 2017 के लिए डॉ. रैकेल अल्मीडा रामोस को उनके शोध प्रबंध के लिए विजेता घोषित किया गया। उनके शोध प्रबंध का विषय

[2]ट्रेडमैप, आईटीसी जेनेवा
[3]https://www.brics2017.org/English/China2017/Theme/
[4]http://www.bricschn.org/English/2017-09/05/c_136583711.htm

वित्तीयकरण और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की विनिमय दरों के निर्धारण पर इसके प्रभाव था। विजेता को चाइना डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष श्री हू ह्वेबैंग द्वारा पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार वितरण के दौरान ब्रिक्स के सदस्य विकास बैंकों के प्रमुख मौजूद थे, जिनमें ब्राजीलीयन नेशनल बैंक फॉर इकनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के अध्यक्ष श्री पौलो रबेलो दे केसत्रो, रूस के वेनेशेकोनोम बैंक के प्रथम अध्यक्ष श्री निकोले सेखोम्स्की; भारतीय निर्यात-आयात बैंक के प्रबंध निदेशक श्री डेविड रस्कीना तथा डेवलपमेंट बैंक ऑफ सदर्न अफ्रीका (डीबीएसए) के अध्यक्ष श्री जाबू मोलेकेती उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉ. रामोस के पुरस्कृत शोध प्रबंध पर आधारित एक्ज़िम बैंक के प्रासंगिक आलेख का भी विमोचन किया गया।

डॉ. रैकेल अल्मीडा रामोस ने अपनी डॉक्टोरल डिग्री वर्ष 2016 में पेरिस, सोरबोर्न पेरिस साइट, फ्रांस तथा यूनिवर्सिड एस्टड्यूअल दे कैपिनास, ब्राजील से प्राप्त की। इस समय वह पेरिस नॉर्ड, यूनिवर्सिटी पेरिस 13, सोरबोर्न पेरिस साइट, फ्रांस के अर्थशास्त्र विभाग में शोध छात्रा हैं।

पुरस्कृत शोध प्रबंध का संक्षिप्त सारांश

वित्तीयकरण और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की विनिमय दरों के निर्धारण पर इसके प्रभाव

प्रस्तुत शोध प्रबंध के अध्ययन में वित्तीयकरण और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की विनिमय दरों के निर्धारण पर इसके प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। वर्ष 2000 के शुरुआती चरण में अंतरराष्ट्रीय तरलता चक्र की एक नई विस्तारण अवस्था और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को पूंजी प्रवाह की बाढ़ को देखा गया। तब से कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाओं की नई विनिमय दरों में 'एक निरंतर उथल-पुथल' रही है, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थितियों में बदलाव के अनुसार बड़े उतार-चढ़ाव के साथ गिरावट देखी जा रही है।

विनिमय दर की यह गत्यात्मकता मुख्यधारा की विनिमय दर के अनुरूप नहीं है, जो फैट टेल्स 'तथा वॉलेटिलिटी क्लस्टरिंग' जैसी विशेषताओं का पता लगाने में असमर्थ है। उभरती मुद्राओं की दो प्रमुख विशेषताएँ बताती हैं कि अशांति(मुद्रा संकट)के समय बड़े पैमाने पर मुद्राएं क्यों बिकती हैं। पहला, उस मुद्रा को मूल्यांकन के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, और मुद्रा संकट के समय मुद्रा के तरल रूप अर्थात अन्य संपत्ति आदि को प्राथमिकता दी जाती है। दूसरा, उन्हें उन वित्तीय उत्तरदायित्वों के भुगतान के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, जो संकट की स्थिति में उत्पन्न होते हैं तथा जिनकी वित्तीय संकट के समय आपूर्ति की मांग होती है।

अध्ययन के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा का बढ़ता मूल्य तथा उसका प्रभाव (यूएस डॉलर की तुलना में) वित्तीयकरण को परिभाषित करता है। इसका अनुमान नई मुद्रा तथा उत्पाद की तुलना में सर्वमान्य प्रचलित मुद्रा (यूएस डॉलर) से करके लगाया जा सकता है। विश्लेषण में यह पता लगाया गया कि अंतरराष्ट्रीय मानक मुद्रा की अंतर्निहित उत्पादक अर्थव्यवस्था के साथ जो तुलना की जाती है, इस संबंध में अपने ही तर्क का अनुसरण करते हुए विद्वानों ने यह तर्क दिया कि वित्त अब वित्तपोषण व्यापार और उत्पादन करने वाले अपने पूर्व कार्यों से जुड़ा नहीं रहा है। अतिरिक्त' वित्त वृद्धि वित्तीय एकीकरण से जुड़ी रही है, जो कि बड़े पैमाने पर उदारीकरण के साथ बढ़ी है और वित्तीय खाते के साथ-साथ चालू खाते के व्यापार में भी बड़े पैमाने पर महत्त्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। अध्ययन में यह बताया गया कि इस घटना(प्रक्रिया)का आशय पुराने चले आ रहे तर्क के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर (पुन:) उद्भव से है।

नीति के निहितार्थ:-

अपने विभिन्न प्रकार के निवेशों के कारण उभरती मुद्राएं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थितियों के अधीन होती हैं, तथा चूंकि उनकी मांग अंतरराष्ट्रीय लिक्विडिटी अधिमान पर निर्भर होती है, अत: अंत में अपनी मुद्राओं की निम्न तरलता की तुलना प्रचलित मानक मुद्रा से की जाती है। इस संबंध में दो महत्त्वपूर्ण नीतियाँ उभर कर सामने आती हैं।

पहला विकल्प है, केनेशियन सुझाव के अनुसार इंटरनेशनल क्लियरिंग यूनियन' में सुधार की तरह ही आईएमएफएस में भी सुधार लाना। केंद्रीय बैंकों का एक केंद्रीय बैंक स्थापित करना, जो बैंकॉर' की तरह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा जारी करे, तथा देशों के केंद्रीय बैंकों की स्थिति को लिक्विडेट करे। अनुबंधों को नाम देने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा जारी की जाए, जो देशों को अपनी मुद्राओं में व्यापार करने की अनुमति देती हो। यह व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था की असमानताओं को कम कर देती है। जहां अमेरिकी डॉलर एकमात्र मुद्रा है जो पैसे के तीनों कार्य करती है। इस प्रकार यह विकल्प उभरती बाजार अर्थव्यवस्था सहित, प्रत्येक अन्य मुद्रा की अधीनता को कम करता है।

दूसरे विकल्प में देश-स्तर की नीतियाँ आती हैं, जो संरचनात्मक विषमता को देखते हुए दुर्बलता को कम करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। अर्थात इसके मुख्य विकल्प हैं: पूंजी प्रवाह नियंत्रण, विदेशी आस्तियों का भंडार और 'यौगिक प्रबंधन तकनीक'। विश्लेषणानुसार, ये नीतियां उभरती मुद्राओं की दुर्बलताओं के निर्माण में धन प्रबंधकों की नवीन रणनीतियों के प्रभाव को कम करती हैं। तदनुसार, आईएमएफएस की श्रेणीबद्ध प्रकृति से हानिकारक प्रभावों को कम किया जा सकता था, तथा अधिक स्थिर विनिमय दरों और मौद्रिक नीति स्वायत्तता के माध्यम से दीर्घावधि निवेश, व्यापार और वृद्धि के लिए महत्त्वपूर्ण कदम हैं।

4 भारतीय ऑटोमोबाइल और कलपुर्जा उद्योग: वर्तमान रुझान एवं संभावनाएं

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में कुछ शुरुआती मूल प्रतिरूपों के बाद से गाड़ियों तथा कलपुर्जों के साथ-साथ कार उद्योग में सतत विकास हुआ है। आज यह उद्योग इतना गतिशील हो गया है कि औद्योगिक देशों में यह लगभग 10 में से 1 व्यक्ति को रोजगार देता है। यहां तक कि विकासशील देशों में भी इस क्षेत्र में नित नए अवसरों का विकास हो रहा है, विशेषतया उन विस्तृत संबंधों के कारण जो कार उद्योगों को अन्य क्षेत्रों से जोड़ते हैं।

उत्पाद और व्यवसाय

मजबूत आर्थिक सक्रियता तथा बुनियादी ढांचे विकास के चलते भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग काफी हद तक अच्छी रफ्तार से उभरा है। सस्ते दामों तथा आसान ऋण सुविधाओं की उपलब्धता के कारण मध्यम वर्ग में भी इसका रुझान काफी बढ़ा है। कारखानों में कार, बहुपयोगी वाहन, हल्के व्यापारिक वाहन, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड तथा रिक्शा और ऑटो इत्यादि लगभग सभी आवश्यक वाहनों का निर्माण होता है। आज भारत विश्वभर में ट्रैक्टरों का सबसे बड़ा उत्पादक है। वहीं दुपहिया वाहनों और बसों के मामले में दूसरा, भारी ट्रकों का पाँचवाँ, कार निर्माण का छठा तथा व्यापारिक वाहनों का आठवाँ सबसे बड़ा निर्माता है।

वर्ष 2011-12 से 2016-17 के दौरान भारतीय वाहनों के उत्पादन में 4.43% सीएजीआर दर्ज की गई। वर्ष 2016-17 में कुल वाहनों के उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा दुपहिया वाहनों का है, जो 79% है। इसके बाद 15% हिस्सा यात्री वाहनों का है। तिपहिया वाहनों तथा व्यापारिक वाहनों का हिस्सा 3% है। संभवतः वर्ष 2026 तक उत्पादन मात्रा की दृष्टि से भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन जाए[5]। भारत से वाहनों का निर्यात, वर्ष 2010-11 के 12.97% से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 13.74% हो गया है, जो भारतीय वाहन उद्योग के अंतरराष्ट्रीय मानदंडों तक पहुंचने की संभावनाओं को बढ़ाता है तथा विश्व बाजार में भारत में निर्मित वाहनों के बढ़ने का संकेत देता है।

वर्ष 2017 में अप्रैल-सितंबर माह के दौरान भारत के कुल वाहन उत्पादन में 9.18% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष यात्री वाहनों की घरेलू बिक्री में अप्रैल-सितंबर 2017 में 9.16 की वृद्धि दर्ज की गई, व्यापारिक वाहनों में 5.96% तथा दुपहिया वाहनों की बिक्री में 10.14% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017 में अप्रैल-सितंबर माह में तिपहिया वाहनों की बिक्री में (-) 9.89% की गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2017 में अप्रैल-सितंबर में कुल वाहनों के निर्यात में 10.71% की वृद्धि हुई। दुपहिया तथा तिपहिया वाहनों के निर्यात में क्रमश: 15.22% तथा 19.42% की वृद्धि हुई, जबकि वर्ष 2017 में अप्रैल-सितंबर में यात्री वाहन तथा व्यापारिक वाहनों के निर्यात में क्रमश: (-) 1.34% तथा (-) 28.53% की गिरावट देखी गई।

पिछले कुछ वर्षों में भारत के कल-पुर्जा उद्योग में भी अच्छा विकास देखा गया है। ग्राहकों की भावना में सुधार, बेहतर बाजार और वित्तीय बाजार में पर्याप्त तरलता इस वृद्धि के कारक हैं। भारतीय कल-पुर्जा उद्योग का कारोबार वर्ष 2011-12 में 42.2 अरब यूएस डॉलर से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 43.5 अरब यूएस डॉलर हो गया है। भारत से कल-पुर्जों का निर्यात वर्ष 2011-12 में 8.8 अरब यूएस डॉलर से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 10.9 अरब यूएस डॉलर हो गया है। अर्थात इसमें 4.37% की सीएजीआर दर्ज की गई।

सरकारी उपक्रम

भारत सरकार ऑटोमोबाइल क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करती है, तथा ऑटोमैटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देती है। इस दिशा में भारत सरकार द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

- सड़क और जल परिवहन के लिए जैव ईंधन वाले वाहनों को आरंभ करने की योजनाएं। भारत को जीवाश्म ईंधन के आयात में कटौती करने और मेथनॉल जैसे सस्ते ईंधनों वाले विकल्प खोजने की आवश्यकता है।
- 'मेक इन इंडिया' की पहल करते हुए भारत में ऑटोमोबाइल निर्माण के उद्देश्य को पूरा करना। ऑटो मिशन योजना (एएमपी) में दर्शाए अनुसार, अनुमान है कि वर्ष 2026 तक यात्री वाहन की मांग में लगभग 9.4 मिलियन यूनिट की वृद्धि हो सकती है।
- देश में सस्ते, अच्छे और विश्वसनीय इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के प्रगतिशील विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय विद्युत परिवर्तन योजना 2020 के अंतर्गत, देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के तीव्र निर्माण के लिए सरकार ने योजना तैयार की है।

संभावनाएँ

एएमपी वर्ष 2016-26 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026 तक वाहनों की बिक्री 66 लाख यूनिट तक पहुंचने की संभावना है। भारतीय ऑटोमोटिव बाजार में करीब 10-15 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान है, जो वर्ष 2016 में करीब 7 अरब डॉलर के आसपास थी और वर्ष 2021 तक 16.5 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। भारतीय वाहन क्षेत्र में वर्ष 2026 तक उत्पादन बढ़कर 300 अरब यूएस डॉलर का होने, 65 मिलियन रोजगार देने तथा भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 12% की वृद्धि होने की क्षमता है।

एक स्थिर नीति का प्रारूप, बढ़ती क्रय शक्ति, बड़े घरेलू बाजार और बुनियादी ढांचे में निरंतर विकास के कारण भारत वाहन उत्पादन के क्षेत्र में एक अनुकूल स्थान बन गया है।

[5]सरकार और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मेनयुफेकचर्स (एसआईएएम) द्वारा तैयार की गई वर्ष 2016-26 के ऑटोमोटिव मिशन योजना के अनुसार,

कच्चा (क्रूड) तेल तथा पेट्रोलियम उत्पाद: हालिया रुझान एवं परिदृश्य

तेल ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसका वैश्विक स्तर पर खपत में 2016 में तीसरा स्थान रहा। ऊर्जा की बीपी सांख्यिकीय समीक्षा (बीपी स्टेरटिस्टीशकल रिव्यूप ऑफ एनर्जी, 2017) के अनुसार वर्ष 2016 में वैश्विक स्तर पर तेल का उत्पादन एवं खपत क्रमशः 4382.4 मिलियन टन तथा 4418.2 मिलियन टन रहा, जिसमें वर्ष 2015 की तुलना में क्रमशः 0.3 प्रतिशत तथा 1.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तेल अधिक समय तक नहीं रहने वाला एक सीमित संसाधन है। वर्ष 2016 के अंत में उत्पादन के अनुपात में तेल उत्पादन 50.6 रहा यानी यदि तेल का उत्पादन वर्तमान दर पर होता रहा तो यह अगले 51 वर्षों तक ही चल पाएगा।

उत्पादन एवं व्यापार

भारत में रिफायनरियों एवं फ्रैक्शयनेटरों द्वारा पेट्रोलियम उत्पा दन में तेजी से वृद्धि हुई है। भारत ने तेल उत्पादन में लंबा सफर तय किया है। 1998–99 में भारत का कुल तेल उत्पातदन 68.4 मिलियन मीट्रिक टन था, जो 2016–17 में बढ़कर 242.7 मिलियन मीट्रिक टन हो गया। 1998–99 में 68.5 मिलियन मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2016–17 में रिफायनरियों द्वारा 245.4 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल को प्रसंस्कृत किया गया।

भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पांदन में 1998–99 से वर्ष 2016–1% के दौरान 7.29 प्रतिशत सीएजीआर से वृद्धि दर्ज की गई। वहीं दूसरी ओर, इसी अवधि में कच्चे तेल को प्रसंस्कृत करने में 7.34 प्रतिशत सीएजीआर से वृद्धि हुई। नीचे दिए गए परिशिष्ट में रिफायनरियों तथा फ्रैक्शलनरों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन तथा रिफायनरियों द्वारा कच्चे तेल के प्रसंस्करण के रुझानों को दर्शाया गया है।

वर्ष 2016–17 के दौरान भारत ने 16.2 बिलियन यूएस डॉलर के पेट्रोलियम उत्पादों का आयात तथा 31.7 बिलियन यूएस डॉलर का निर्यात किया। भारत से सबसे ज्याोदा पेट्रोलियम निर्यात सिंगापुर को किया गया जिसका शेयर 15.0 प्रतिशत रहा, इसके बाद यू ए ई (12.1 प्रतिशत), यू एस ए (5.9 प्रतिशत) तथा नीदरलैंड (4.5 प्रतिशत) का स्थान रहा। वहीं कतर से सर्वाधिक 31.5 प्रतिशत शेयर के साथ तेल आयात करने वाला देश भारत है, उसके बाद यू ए ई (16.1 प्रतिशत), सऊदी अरब (11.62 प्रतिशत) तथा यू एस ए (7.2 प्रतिशत) का स्थान रहा।

वर्ष 2016–17 के दौरान कच्चे तेल के लिए भारत का आयात बिल 86.9% बिलियन यूएस डॉलर रहा। 17.9 प्रतिशत शेयर के साथ सऊदी अरब सबसे बड़ा आयात स्रोत रहा। इसके बाद इराक (13.4 प्रतिशत), तथा यूएई (10.4 प्रतिशत) का स्थान रहा।

सरकारी पहलें

तेल एवं गैस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

- सरकारी तेल कंपनियां स्वच्छ ऊर्जा एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एल पी जी) इंफ्रास्ट्रक्चर में बोली उत्तर प्रदेश में 723 करोड़ रुपए (111.30 मिलियन यू एस डॉलर) का निवेश करने की योजना बना रही हैं।
- परिवहन ईंधन में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई पॉलिसी तैयार करने तथा कुल मूल्य श्रृंखला में 1 लाख करोड़ रुपए (15.64 अरब यू एस डॉलर) का निवेश करने की योजना है।
- राजस्थान में 9 मिलियन टन क्षमता तथा महाराष्ट्र में 60 मिलियन टन क्षमता वाली रिफायनरी तैयार करने की योजना है। तेल व गैस क्षेत्रों की नीलामी, LPG के उपयोग को बढ़ाना तथा भारत में निवेश के लिए सऊदी अरब की तेल कंपनी (सऊदी अरामको) के साथ वार्ता।
- आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार की कैबिनेट समिति ने छोटी–छोटी तेल एवं गैस क्षेत्र की कंपनियों का पता लगाकर जो ऑइल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) तथा ऑइल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) से संबद्ध हैं, को 23 ऑनशोर तथा 8 ऑफशोर संविदा प्रदान करने हेतु मंजूरी प्रदान की है।

संभावनाएं

भारत में 2040 तक तेल की मांग 3.6 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़कर 458 मिलियन टन तेल के समतुल्य पहुंचने की उम्मीद है। वहीं, ऊर्जा की मांग में दोगुनी से ज्यादा होने का अनुमान है। इसका मुख्य कारण अर्थव्यवस्था के वर्तमान की तुलना में 5 गुना बढ़ने की उम्मीद है।

सरकार द्वारा उठाए गए हालिया कदमों के साथ–साथ तेल की कम कीमतों के सकारात्मक प्रभावों, जैसे– चालू खाता संतुलन में सुधार, के चलते घरेलू और वैश्विक स्तर पर भारत निवेश के लिए पसंदीदा स्थल बनकर उभरा है।

चार्ट: भारत में पेट्रोलियम उत्पारदों का उत्पादन एवं कच्चे तेल का प्रसंस्करण

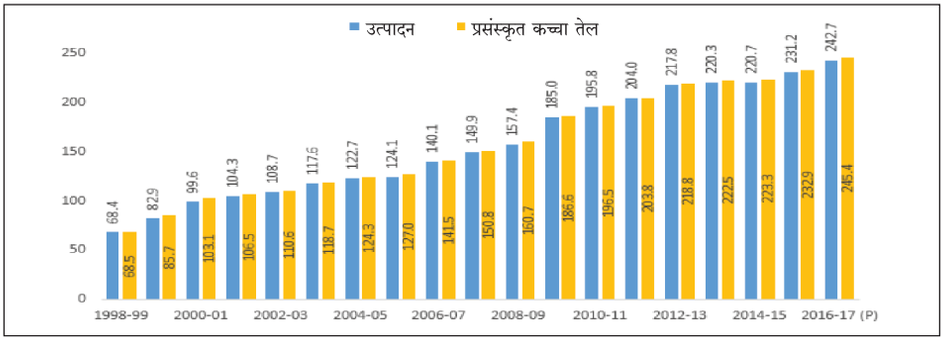

स्रोतः पेट्रोलियम आयोजना एवं विश्लेषण विभाग, एक्ज़िम बैंक शोध

[6]उत्पोदन की तुलना में भंडार अनुपात (आर/पी अनुपात) – यदि किसी साल के अंत में शेष भंडार को उस वर्ष के उत्पादन से भाग दें तो यह परिणाम निकल आएगा कि जो सुरक्षित भंडार है वह उसी उत्पादन दर पर कितनी समयावधि तक चलने वाला है।

[7]उपयोग की गई विनिमय दर– यथा 16 नवंबर, 201% को 1 भारतीय रुपया = 0.215 यूएस डॉलर

[8]पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

6 बिम्सटेक देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार

बिम्सटेक की पृष्ठ भूमि

बिम्सटेक को प्रारम्भ में बिम्सटेक (बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाइलैंड- आर्थिक सहयोग) कहा जाता था, जिसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा के जरिए की गई थी। दिसंबर 1997 में म्यांमार को इसमें शामिल करने के बाद इस संगठन का नाम बदलकर बीआईएमएसटी-ईसी हो गया। फरवरी 2004 में थाइलैंड में मंत्रियों की बैठक के बाद इसका नाम बदलकर बिम्स टेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल)[9] रख दिया गया।

06 जून, 2017 को बिम्सटेक ने अपनी स्थापना का 20वां वर्ष पूरा किया। बिम्सटेक शब्द बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका तथा थाइलैंड से मिलकर बना है जिसकी आबादी सम्मिलित रूप से 1.65 अरब[10] है, जो विश्वि की कुल आबादी का 22.3 प्रतिशत है तथा इसका संयुक्त जीडीपी 3.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर है जो 2016 में वैश्विक जीडीपी (75.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर)[11] की 4.1 प्रतिशत है। बिम्सटेक के दोनों ओर से दक्षिण एशिया (भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एवं श्रीलंका) तथा दक्षिण पूर्व एशिया (म्यांमार एवं थाइलैंड) से घिरा होने के कारण सबसे ज्यादा लाभ मिलता है तथा यह सार्क एवं एशियाई सदस्यों के बीच अंतःक्षेत्रीय व्यापार एवं सहयोग के लिए एक सामान्य प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है।

बिम्सटेक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार

बिम्सटेक देशों के साथ भारत के व्यापार में सतत वृद्धि हुई है जो वर्ष 2011-12 के 23.3 अरब यू एस डॉलर से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 29.5 अरब यू एस डॉलर हो गया है। हालांकि इस अवधि के दौरान बिम्सटेक देशों से भारत का आयात अपरिवर्तित रहा है। किन्तु बिम्स टेक देशों को निर्यात में वर्ष 2011-12 के 14.6 अरब यूएस डॉलर की तुलना में वर्ष 2016-17 में 20.9 अरब यूएस डॉलर की तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद बिम्सटेक देशों के साथ भारत का व्यापार अधिशेष वर्ष 2011-12 के 6 अरब यूएस डॉलर से बढ़कर 2016-17 में 12.4 अरब यूएस डॉलर हो गया।

वर्ष 2016-17 में भारत-बिम्सटेक व्यापार भारत के कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 4.5 प्रतिशत रहा। जबकि भारत के कुल निर्यातों में से बिम्सटेक को 7.6 प्रतिशत निर्यात किया गया। भारत के कुल आयातों में से बिम्सटेक से मात्र 2.2 प्रतिशत आयात किया गया। बिम्सटेक देशों में से थाइलैंड भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है जिसका वर्ष 2016-17 में भारत से बिम्स टेक के साथ हुए कुल व्यापार में से 29 प्रतिशत व्यापार हिस्सा है। इसके बाद 25.5 प्रतिशत व्यापार के साथ बांग्लादेश का स्थान है।

बिम्स टेक मुक्त व्यापार क्षेत्र फ्रेमवर्क करार पर 2004 में हस्ताक्षर हुए थे, किन्तु इन क्षेत्रों में सामंजस्य की कमी जैसे टैरिफ में कटौती के तौर तरीके तथा उन्मूलन, नकारात्मक सूची का आकार, नियम लागू करने के मानदंड, मतभेद निपटान प्रक्रिया, संरक्षण नितियां, सीमा शुल्क संचालन तथा सेवा एवं निवेश करारों पर बातचीत में कमी की वजह से यह परिचालन में नहीं आ पाया। इस फ्रेमवर्क करार में माल एवं सेवाएं, निवेश, आर्थिक सहयोग के साथ-साथ व्यापार सुगमीकरण एवं बिम्सटेक में अल्प विकसित देशों (एल डी सी) के लिए तकनीकी सहायता भी शामिल होने की उम्मींद है।

बिम्स टेक देशों में भारत का निवेश

निवेश की दृष्टि से गत दशक में भारत द्वारा बिम्सटेक देशों में निवेश में वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2006 तथा 2016 के बीच इन क्षेत्रों में भारत का एफडीआई जावक 2.2 अरब यूएस डॉलर रहा तथा इस अवधि के बाद ओएफडीआई धीरे-धीरे बढ़ा है।

भारत का ओएफडीआई प्रमुख रूप से तीन देशों बांग्लादेश, थाईलैंड तथा श्रीलंका में केन्द्रित है।[12] बांग्ला देश में भारत ने ऊर्जा, टेक्सटाइल, औषधि, ऑटोमोटिव, उपभोक्ता वस्तुएं तथा दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में निवेश किया है। वहीं दूसरी ओर, थाइलैंड में भारत ने कृषि उत्पादों, खनिज एवं सिरैमिक, धातु उत्पाद तथा मशीनरी, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रिक उत्पादों, रसायन तथा टेक्सटाइल के क्षेत्रों में निवेश किया है। श्रीलंका में निवेश करने वाले शीर्ष चार निवेशकों में भारत भी है। भारत का निवेश पेट्रोलियम, रिटेल, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, भूमि-भवन (रियल एस्टेट), दूरसंचार, आतिथ्य एवं पर्यटन, बैंकिंग तथा खाद्य प्रसंस्करण (चाय एवं फल जूस), धातु उद्योग, टायर, सीमेंट, शीशा निर्माण तथा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास (रेलवे, बिजली एवं जल आपूर्ति) जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है।[13]

भारत, नेपाल तथा म्यांमार में सबसे बड़ा निवेशक है। नेपाल में मंजूर कुल एफडीआई का लगभग 40 प्रतिशत कुछ प्रमुख क्षेत्रों जैसे विनिर्माण, सेवाएं (बैंकिंग, बीमा, ड्राई पोर्ट, शिक्षा एवं दूरसंचार), बिजली क्षेत्र तथा पर्यटन उद्योग में निवेश किया गया है तथा म्यांमार में प्रमुख रूप से तेल एवं गैस तथा बैंकिंग क्षेत्र में दसवां सबसे बड़ा निवेशक बन गया है।

भारत-बिम्स टेक संबंधः हालिया पहल

पंद्रहवीं बिम्स टेक मंत्रीमंडलीय बैठक 10-11 अगस्त, 2017 को काठमांडू, नेपाल में आयोजित की गई थी। भारत की विदेश मंत्री के वक्तव्य को इस पहल के लिए व्यापक स्तर पर दर्शाया गया कि भारत विभिन्नि क्षेत्रों में उच्च स्तरीय सम्मेलनों; व्यापार एवं पर्यटन प्रदर्शनियों, इस क्षेत्र की कंपनियों के साथ मिलकर नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए शिखर सम्मेलनों तथा निवेश के लिए तैयार परियोजनाओं को चालू करने के लिए पहल कर रहा है। इन पहलों से न सिर्फ व्यापार, निवेश, नवोन्मेष तथा जन-जन से संपर्क को बल मिलेगा बल्कि इससे ''ब्रांड बिम्सटेक'' की पहुंच बढ़ेगी।

चार्टः बिम्स टेक देशों के साथ भारत का व्यापार (अरब यूएस डॉलर)

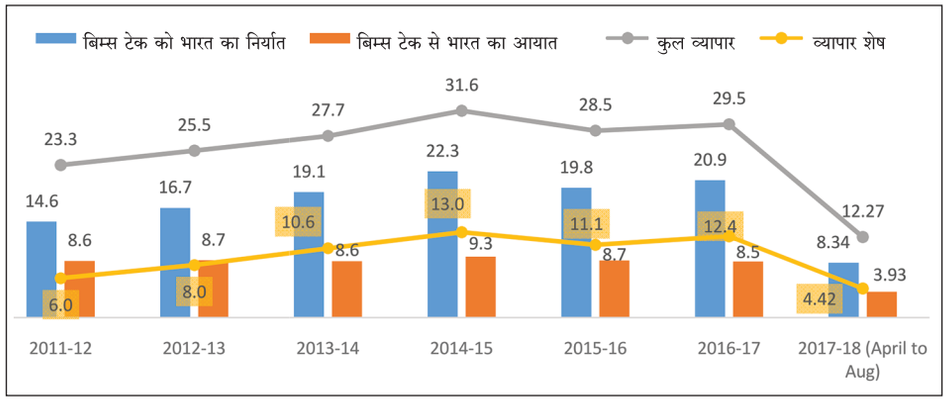

स्रोतः वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

[9]www.bimstec.org/overview

[10]विश्व विकास संकेतक, विश्व बैंक

[11]विश्व आर्थिक मंच अप्रैल 201% डेटाबेस, आईएमएफ

[12]बिम्सटेकः द रोड अहैड, आरआईएस रिपोर्ट 2016

[13]भारत के द्विपक्षीय संबंधः सार संक्षेप, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

संक्षिप्त विवरण

आज विश्व जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितताओं की वजह से धीरे-धीरे सचेत हो रहा है। इस तरह की परिस्थिति में, अपनाई जाने वाली रणनीतियों में प्रमुख रूप से ऐसी पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं को बड़े पैमाने पर उपयोग बढ़ाना है, जिससे पर्यावरणीय क्षति की रोकथाम के साथ-साथ इसे और खराब होने से बचाया जा सके। इस संदर्भ में ''पर्यावरण वस्तु अनुकूल'' क्या- है, इसकी पहचान करना महत्व पूर्ण हो जाता है, जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारकों को कम करने में मदद कर सके।

पर्यावरण से संबंधित वस्तुओं पर सबसे पहले चर्चा दोहा में नवंबर 2001 में आयोजित विश्व व्यापार संगठन (डब्यू टी ओ) की मंत्रीमंडलीय बैठक के दौरान की गई थी। इस बैठक में व्यापार एवं पर्यावरण से जुड़े कुछ मुद्दों पर बातचीत करने की सहमति बनी थी। दोहा कार्य योजना के पैराग्राफ 31 (iii) में इस बातचीत के अधिदेश को पर्यावरणीय वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए टैरिफ एवं गैर-टैरिफ बाधाओं के उन्मूलन को ''कटौती या उपयुक्त'' कहा गया। इसके बाद, व्यापार एवं पर्यावरण समिति (सी टी ई एस एस) द्वारा आयोजित विशेष सत्र के तहत पर्यावरणीय वस्तुाओं को सूचीबद्ध कर लिया गया, जो डब्यूटीओ के अंतर्गत काम करता है।

इस कार्यवाही की वजह से बातचीत में दो बार काफी अहम बदलाव आए:

- पहला, जब 2009 में संयुक्त रूप से ''फ्रेंड्स ऑफ एन्व्यारनमेंट गुड्स ग्रुप[14]'' द्वारा 153 वस्तुओं की व्यापक सूची तैयार की गई, जिसे फ्रेंड्स लिस्टू के नाम से भी जाना गया; तथा
- दूसरा, जब डब्यूटीओ मल्टीलैटरल से प्लूरीलैटिरल बातचीत पहल को पर्यावरणीय वस्तुओं में परिवर्तित करने हेतु तैयार किया गया। यह घोषणा की गई कि देश बातचीत के शुरुआत में ही 54 पर्यावरणीय वस्तुओं को एपेक सूची से बाहर कर देगा। सबसे मजेदार बात यह है कि एपेक सूची में शामिल 54 में से 48 वस्तुएं तो वे ही हैं जिन्हें ''फ्रेंड्स लिस्टर'' के अंतर्गत प्रस्तावित 153 वस्तुओं में शामिल किया जाना प्रस्तावित है।

फ्रेंड्स लिस्ट के अंतर्गत चिह्नित 153 ईजी वस्तुओं का विश्लेषण

153 पर्यावरणीय अनुकूल वस्तुओं में से फ्रेंड्स लिस्ट में चिह्नित मदों का 2015 में निर्यात 960.1 अरब यूएस डॉलर का रहा, जबकि भारत का निर्यात 9.8 अरब यूएस डॉलर का था। वैश्विक स्तर पर इन मदों के निर्यात में भारत का शेयर लगभग 1 प्रतिशत रहा। वैश्विक स्तर पर, वर्ष 2015 में 153 ईजी के शीर्ष निर्यातकों में चीन (16%), जर्मनी (14%), यूएस (12%), जापान (6%) तथा इटली (5%) (चार्ट 1) हैं।

निर्धारित फ्रेंड्स लिस्ट) के अनुसार, 2011 से 2015 के दौरान (एचएस कोड के तहत 153 वस्तुओं) का भारत के निर्यात में 4.3 प्रतिशत की एएजीआर से वृद्धि दर्ज की गई तथा यह 8.3 अरब यूएस डॉलर से बढ़कर 9.7 अरब यूएस डॉलर हो गया। हालांकि इस अवधि के दौरान आयात (-) 1 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 17.7 अरब यूएस डॉलर से घटकर 16.8 अरब यूएस डॉलर हो गया।

चार्ट 1- फ्रेंड्स लिस्ट (2015) के तहत 153 ई जी के प्रमुख वैश्विक निर्यातक

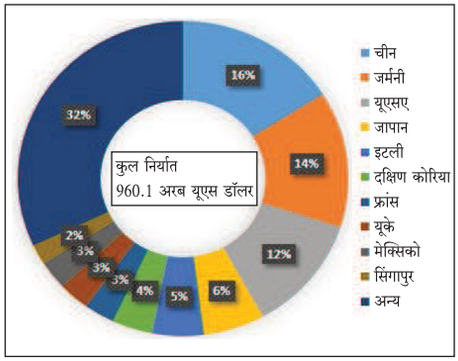

स्रोतः यूएन कॉमट्रेड के आंकड़े;
एक्ज़िम बैंक शोध

153 वस्तुओं की फ्रेंड्स लिस्ट में से ई जी वस्तुओं का वर्ष 2015 में भारत द्वारा प्रमुख रूप से यूएस (17%), यूएई (7%), यूके (5%), सउदी अरब (4%) तथा जर्मनी (4%) को निर्यात किया गया। भारत से 153 ई जी वस्तुओं का शीर्ष 10 देशों को निर्यात कुल निर्यात का 52% रहा। वहीं, 2015 में जिन देशों से भारत ने इन वस्तुओं का आयात किया, उनमें चीन (31%), जर्मनी (13%), यूएसए (11%), जापान (7%) तथा दक्षिण कोरिया (5%) शामिल रहे। भारत द्वारा 153 ई जी वस्तुओं के कुल आयात का 81% शीर्ष दस देशों से आयात किया गया।

एपेक सूची के अंतर्गत चिह्नित 54 ई जी वस्तुओं का विश्लेषण

एपेक सूची में ई जी के रूप में चिह्नित वस्तुओं का वैश्विक निर्यात 2015 में 492.4 अरब यूएस डॉलर रहा, जबकि भारत का निर्यात 3.1 अरब यूएस डॉलर रहा। यानी इन चिह्नित वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में देश का हिस्सा 0.64% रहा। वैश्विक स्त र पर 153 ई जी वस्तुओं की एपेक सूची के लिए 2015 में शीर्ष निर्यातक चीन (18%), जर्मनी (12%), यूएस (12%), दक्षिण कोरिया (8%) तथा जापान (7%) रहे। (चार्ट 2)।

54 ई जी वस्तुओं के लिए भारत का व्यायपार घाटा वर्ष 2015 में 6.4 अरब यूएस डॉलर रहा। ई जी वस्तुओं का भारत द्वारा आयात 2015 में 9.6 अरब यूएस डॉलर का रहा, जबकि निर्यात 3.1 अरब यूएस डॉलर ही रहा। वर्ष 2011 से 2015 के दौरान भारत से ई जी वस्तुओं के निर्यात में 1.4 प्रतिशत की एएजीआर से वृद्धि दर्ज की गई, जबकि आयात में (-) 0.2% की गिरावट दर्ज की गई।

चार्ट 2- एपेक सूची (2015) के अंतर्गत ई जी वस्तुओं के प्रमुख वैश्विक निर्यातक

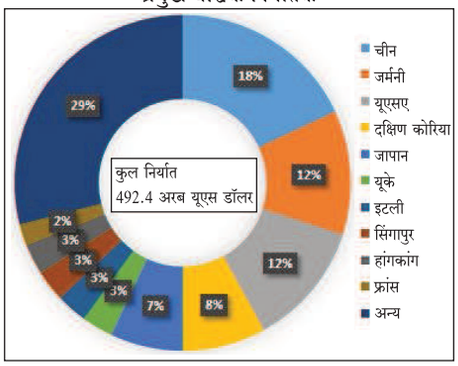

स्रोतः यूएन कॉमट्रेड के आंकड़े;
एक्ज़िम बैंक शोध

भारत में पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए संभावित पहलें

भारत में पर्यावरणीय अनुकूल वस्तुओं की वृद्धि में तेजी लाने के लिए बहुत से विकल्प हैं। इनमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण बढ़ाना, वस्तुओं के इस्तेमाल के अनुसार उन पर शुल्क वापसी, निवेश आकर्षित करना और उसे सुगम बनाना और विभिन्न टैरिफों में धीरे-धीरे कमी करने जैसे विकल्प शामिल हैं।

भारत से इन वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि समुचित नीतियों के जरिए पर्यावरणीय वस्तुओं की निर्यात क्षमता बढ़ाई जाए। इससे इस क्षेत्र में व्यापक स्तर पर निवेश आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी। यदि अंतिम उपयोग वाली वस्तुओं पर आधारित पर्यावरणीय उत्पादों में ऐसे उत्पाद भी शामिल किए जाते हैं, जिनमें विकासशील देशों के लिए वृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है या वृद्धि की संभावना है तो निर्यात से होने वाली आय के लिए इन वस्तुओं को बढ़ावा दिया जा सकता है।

इन वस्तुओं के क्षेत्र में निवेश को सुगम बनाने का एक और उपाय यह भी है कि अन्य क्षेत्रों में किए गए नीतिगत उपायों को देखा जाए कि उनमें से कौन से उपाय इन वस्तुओं के क्षेत्र में भी लागू किए जा सकते हैं। ऐसा ही एक उपाय भारत में ऑटोमोटिव क्षेत्र के विकास के लिए अपनाया गया पॉलिसी फ्रेमवर्क हो सकता है, जिसके लिए यह माना जाता है कि इससे अपार सफलता मिली है।

पर्यावरणीय वस्तु करार के अंतर्गत जारी विर्मश में, चिह्नित वस्तुओं के दोहरे अथवा बहु उपयोग जैसे मसले सामने आए हैं। इसलिए ऐसे उत्पादों की मांग है जो इसके उद्देश्यों के अनुरूप हों। इसके लिए एक संभावित समाधान यह हो सकता है कि सरकार या सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य संस्था, विशिष्ट परियोजनाओं के लिए इन वस्तुओं के आयात पर दिए गए शुल्क को रिफंड कर सके, जिससे जलवायु परिवर्तन या पर्यावरणीय क्षति को रोकने में भी मदद मिलेगी।

यदि इन उपायों को क्रियान्वित किया जाए तो इससे पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं के क्षेत्र में निर्यात का हिस्सा बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

[14]देशों की सूची में कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान, कोरिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पाइपेई, स्विट्जरलैंड और अमेरिका शामिल हैं।देशों की सूची में कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान, कोरिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पाइपेई, स्विट्जरलैंड और अमेरिका शामिल हैं।

8 भारत–म्यांमार व्यापार पर एक नजर

भारत और म्यांमार सीमावर्ती देश हैं। दोनों देशों की सीमा 1600 किलोमीटर तक साथ-साथ लगती है। बंगाल की खाड़ी में दोनों की समुद्री सीमा मिलती है। पूर्वोत्तर के चार राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा म्यांमार से लगती है। दोनों देशों की धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक साझी विरासत है। आसियान देशों में से म्यांमार एकमात्र देश है, जिसकी सीमा भारत से लगती है और इसलिए यह दक्षिण पूर्व एशिया के लिए प्रवेश द्वार है। इस तरह यह भारत की लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट नीति के जरिए बेहतर आर्थिक एकीकरण का माध्यम भी बनता है।

1970 में भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। म्यांमार के साथ भारत का कुल व्यापार 2007-08 के 1 अरब यूएस डॉलर से बढ़कर 2016-17 में 2.2 अरब यूएस डॉलर हो गया। म्यांमार को भारत का निर्यात 19.5 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा। 2007-08 में यह 0.2 मिलियन यूएस डॉलर था, जो 2016-17 में बढ़कर 1.1 अरब यूएस डॉलर का हो गया। म्यांमार से भारत का आयात भी 2.8 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा। 2007-08 में यह 0.8 अरब यूएस डॉलर का था, जो 2016-17 में बढ़कर 1.1 अरब यूएस डॉलर का हो गया। तदनुसार, म्यांमार के साथ भारत का व्यापार संतुलन 2007-08 के 0.6 अरब यूएस डॉलर के घाटे से 40.7 मिलियन यूएस डॉलर के सरप्लस में बदल गया।

2016-17 में भारत से म्यांमार को निर्यात की गई प्रमुख वस्तुओं में चीनी और मिठाइयां (कुल आयातों का 38.1 प्रतिशत) रहीं। इसके बाद फार्मास्युटिकल उत्पादों (16.6 प्रतिशत) का स्थान रहा, रेलवे अथवा ट्रामवे के अलावा यातायात के साधन (5.8 प्रतिशत), इलेक्ट्रिकल मशीनरी और मैकेनिकल उपकरण (4.2 प्रतिशत) और कपास (3.7 प्रतिशत)।

2016-17 के दौरान म्यांमार से भारत द्वारा प्रमुख आयातित वस्तुओं में सब्जियां और कंद-मूल (कुल आयात का 75.8 प्रतिशत), लकड़ी और लकड़ी की वस्तुएं (14.6 प्रतिशत), विमान, अंतरिक्ष यान और पुर्जे (4.6 प्रतिशत), फल और मेवा (1.7 प्रतिशत) और कॉफी, चाय तथा मसाले (0.9 प्रतिशत) का स्थान रहा।

भारत, म्यांमार का पांचवां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, लेकिन अनौपचारिक व्यापार के चलते यह अपनी पूरी क्षमताओं के अनुकूल नहीं है। भारत-म्यांमार सीमा व्यापार अपनी क्षमता से कम होने की एक वजह बैंकिंग और संबंधित सेवाओं का अभाव है, जो सीमा पर औपचारिक व्यापार के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों के बाजार आम तौर पर विदेशी उपभोक्ता वस्तुओं से भरे रहते हैं, जो इन बाजारों तक कानूनी तरीकों के अलावा दूसरे चैनलों से पहुंचती हैं।[15] पूर्वोत्तर में नौ लैंड कस्टम स्टेशनों (एलसीएस) पर किए गए फील्ड सर्वे से पता चलता है कि एलसीएस को बुनियादी ढांचे की कमी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की अनुपलब्धता, खराब सड़कें और माल की मैनुअल हैंडलिंग, महंगे विनिमय दर तथा अन्य बाधाएं सीमा पर व्यापार को महंगा बना देते हैं।[16] परिणामतः अनाधिकारिक (अनौपचारिक) व्यापार तेजी से फैलता गया। सीमा पर उच्च ट्रांजैक्शन लागत को व्यापार सुगमीकरण उपायों और नीतियों के जरिए कम किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत एक उपाय क्लीयरेंस देने वाली एजेंसियों की संख्या को कम करना भी हो सकता है।

व्यापार और निवेश के लिए बैंकिंग क्षेत्र में समन्वय बहुत महत्त्वपूर्ण है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने द्विपक्षीय व्यापार को सुगम बनाने के लिए म्यांमार के बैंकों (एमएफटीबी, एमआईसीबी, एमईबी और 9 निजी बैंकों) के साथ बैंकिंग करार किए हैं। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, एक्ज़िम बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के यांगून में प्रतिनिधि कार्यालय हैं।

कुछ क्षेत्रीय करार भी हैं, भारत और म्यांमार जिनके हिस्से हैं। इसलिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर इसका प्रभाव पड़ता है। ये क्षेत्रीय करार निम्नलिखित हैं:

- **बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक):** यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसमें बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल शामिल हैं। म्यांमार ने बिम्सटेक मुक्त व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए हैं और इस क्षेत्र में ज्यादातर थाईलैंड तथा भारत के साथ व्यापार करता है।

  मेकोंग गंगा कॉपरेशन (एमजीसी): यह पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति, परिवहन और संचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए छह देशों की पहल है, जिसमें भारत और पांच आसियान देश- कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं।

  दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन (सार्क): सार्क 8 दक्षिण एशियाई देशों (अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका) का संगठन है। म्यांमार को अगस्त 2008 में सार्क में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था।

  दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन (आसियान) : म्यांमार एकमात्र आसियान देश है, जिसकी भौगोलिक सीमा भारत से लगती है और यह भारत तथा दक्षिण एशियाई बाजारों के बीच एक पुल का काम करता है।

भारत–म्यांमार के बीच द्विपक्षीय व्यापार (यूएस डॉलर बिलियन)

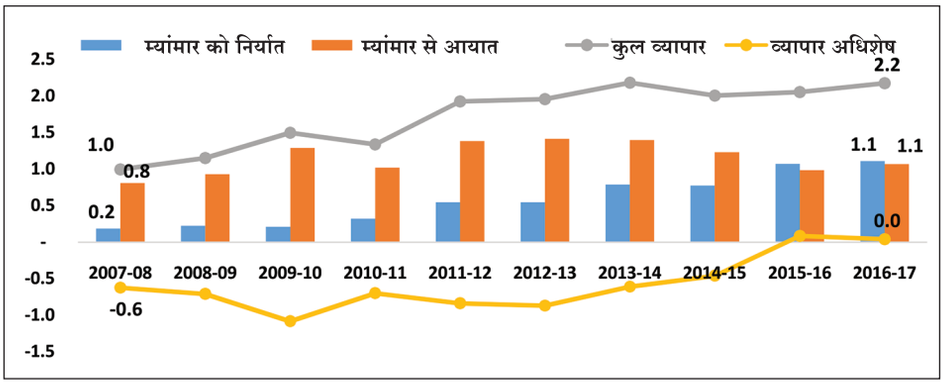

स्रोत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

[15]भारत-म्यांमार सीमा व्यापार को बढ़ानाः नीतिगत तथा कार्यान्वयन उपाय, राम उपेन्द्र दास, 2016

[16]बांग्लादेश और म्यांमार के साथ उत्तर पूर्व भारत के व्यापार और निवेश का विस्तार, आरआईएस, 2011

1. भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने लघु एवं मध्यम उद्यमों पर विशेष बल के साथ भावी बाजार प्रवेश व्यवस्था के रूप में ऋण-व्यवस्थाएं (एलओसी) प्रदान करने पर विशेष जोर दिया है। ये ऋण-व्यवस्थाएं भारतीय निर्यातक समुदाय को जोखिम और दायित्व रहित निर्यात वित्तपोषण का विकल्प प्रदान करती हैं, जो उन्हें नए बाजारों में पहुंच बढ़ाने और मौजूदा विदेशी बाजारों में निर्यात बढ़ाने में मदद करती हैं। एक्ज़िम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और अन्य विदेशी संस्थाओं को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है, जो उन देशों के क्रेताओं को भारत से आस्थगित भुगतान शर्तों पर विकासपरक तथा बुनियादी संरचना परियोजनाओं, उपकरण, माल एवं सेवाओं का आयात करने में समर्थ बनाती हैं। एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के आदेश पर भी ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है। इनके अंतर्गत एक्ज़िम बैंक माल के शिपमेंट पर भारतीय निर्यातक को संविदा मूल्य के 100 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करता है, बशर्ते कि कुल संविदा मूल्य के कम से कम 75 प्रतिशत के माल एवं सेवाओं का शिपमेंट भारत से किया गया हो। ऋण-व्यवस्थाओं के जरिए उभरते बाजारों में भारत की परियोजना निष्पादन क्षमता के प्रदर्शन में भी मदद मिली है। हाल के वर्षों में ऋण-व्यवस्थाओं ने गति पकड़ी है। विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और सीआईएस क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की गई हैं। बैंक द्वारा अब तक अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका ओशिनिया और सीआईएस क्षेत्रों के 63 देशों को 16.86 अरब यूएस डॉलर की 221 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं, जो भारत से निर्यातों के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध हैं। इस प्रकार ऋण-व्यवस्थाएं विकासशील देशों में भारत से परियोजनाओं, माल और सेवाओं के निर्यात के संवर्द्धन और सुगमीकरण के लिए प्रभावी साधन हैं।

2. एक्ज़िम बैंक ने भारत सरकार के सहयोग से जुलाई-सितंबर, 2017 की अवधि के दौरान निम्नलिखित एक ऋण-व्यवस्था करार पर हस्ताक्षर किए:

भारत सरकार की ओर से गयाना सरकार को 17.50 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई। यह ऋण-व्यवस्था गयाना में तीन प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए दी गई है। इस ऋण-व्यवस्था करार सहित एक्ज़िम बैंक अब तक गयाना सरकार को भारत सरकार की ओर से कुल 109.88 मिलियन यूएस डॉलर की आठ ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान कर चुका है। गयाना सरकार को प्रदान की गई ऋण-व्यवस्थाओं के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण, ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम की आपूर्ति और संस्थापना, सिंचाई पंपों की आपूर्ति, अस्पताल, सड़क निर्माण परियोजना, यात्री मालवाहन फेरी वेसल की आपूर्ति और उच्च क्षमता वाले ड्रेनेज पंपों की आपूर्ति जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।

सफलता की कहानी

मॉरिटानिया दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र

- एक्ज़िम बैंक द्वारा मॉरिटानिया सरकार को दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के लिए 21.80 मिलियन यूएस डॉलर की भारत सरकार समर्थित ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई।
- इस दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की क्षमता 30,000 लीटर दूध/प्रतिदिन है।
- इस संयंत्र का उद्घाटन 3 मई, 2016 को हुआ था।
- यह मॉरिटानिया का एकमात्र दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र है।

अधिक जानकारी के लिए
कृपया संपर्क करें :
श्री नदीम पंजेतन,
मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक,
मेकर चेंबर्स IV, 8वीं मंज़िल,
222 नरीमन पॉइंट, मुंबई- 400 021.
टेलीफोन : (22) 22861561
फैक्स : (22) 22823394
ई-मेल : eximloc@eximbankindia.in

तिमाही गतिविधियां

श्री डेविड रस्कीना एक्ज़िम बैंक के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए

श्री डेविड रस्कीना ने भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) के प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। इस नियुक्ति से पहले वह बैंक के उप प्रबंध निदेशक थे और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे।

श्री रस्कीना मुंबई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी में ग्रेजुएट तथा व्यवसाय प्रबंधन में पोस्टर-ग्रेजुएट हैं। उन्होंने 1985 में एक्ज़िम बैंक ज्वॉइन किया था। उन्हें निर्यात ऋण के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। उन्हें बैंक के विभिन्न समूहों ट्रेजरी, बहुपक्षीय निधिक एजेंसी परियोजनाओं, आयोजना एवं शोध, जोखिम प्रबंधन, ऋण-व्यवस्था, व्यापार वित्त, परियोजना निर्यात, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी और कॉर्पोरेट संचार में कार्य का अनुभव है।

श्री रस्कीना खाड़ी सहयोग परिषद के लिए एक निर्यात ऋण एजेंसी की स्थापना हेतु व्यवहार्यता अध्ययन के लिए बनाई गई एक्ज़िम बैंक टीम के एक सदस्य रहे हैं। वह सॉफ्टवेयर इकाइयों को कार्यशील पूँजी ऋण प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित वर्किंग ग्रुप के भी सदस्यट रहे हैं। वह 1999 से 2004 तक बैंक के वाशिंगटन डीसी प्रतिनिधि कार्यालय के निवासी प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। वाशिंगटन में रहते हुए उन्होंने विश्व बैंक द्वारा निधिक परियोजनाओं में प्रोक्योरमेंट संबंधी भारतीय कंपनियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने का काम किया। साथ ही उन्होंने लैटिन अमेरिका/कैरिबियाई क्षेत्रों और बैंकों को निर्यात ऋण-व्यवस्था शुरू करने में सहयोग दिया। 2005 में बैंक के पहले मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में उन्होंने क्रिसिल की सहायता से व्यापक ऋण जोखिम मॉडल सहित जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रणाली की शुरुआत की।

उन्होंने भारत और विदेशों में कई विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विकास बैंकिंग संस्थान सहित विभिन्न बैंक प्रशिक्षण महाविद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों और भारत तथा अमेरिका के औद्योगिक निकायों में उन्होंने निर्यात वित्त पर व्याख्यान भी दिए हैं। वह सीआईआई-एक्ज़िम बैंक व्यवसाय उत्कृष्टता पुरस्कार की राष्ट्रीय निर्णायक समिति के सदस्य हैं। यह यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट के टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट (टीक्यूम) मॉडल पर आधारित एक समग्र गुणवत्ता प्रबंधन पुरस्कार है। श्री रस्कीना एक उत्कृष्ट कम्यूनिकेटर भी हैं तथा भारतीय और विदेशी अखबारों में उनके आलेख प्रकाशित होते रहे हैं।

एक्ज़िम बैंक ने एनईआईए के तहत लैटिन अमेरिका क्षेत्र में सूरीनाम को 8.64 मिलियन यूएस डॉलर का पहला क्रेता ऋण प्रदान किया

एक्ज़िम बैंक ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) के अंतर्गत लैटिन अमेरिका क्षेत्र में सूरीनाम गणराज्यअ को 8.64 मिलियन यूएस डॉलर का पहला क्रेता ऋण प्रदान किया। यह क्रेता ऋण सूरीनाम में किर्लोस्कर ब्रदर्स लि., इंडिया द्वारा निष्पादित वागनिंगन पंपिंग स्टेशन के लिए तीन पंपों तथा संबद्ध सामानों एवं सेवाओं की आपूर्ति संबंधी संविदा के वित्तपोषण के लिए दिया गया है। इस संबंध में बीसी-एनईआईए करार पर पारामारिबो, सूरीनाम में 18 अगस्त, 2017 को सूरीनाम गणराज्य सरकार के माननीय वित्त मंत्री श्री गिलमोर होफड्रेड तथा एक्ज़िवम बैंक की ओर से वाशिंगटन डीसी प्रतिनिधि कार्यालय के निवासी प्रतिनिधि श्री शैलेष प्रसाद द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर सूरीनाम में भारत के माननीय राजदूत श्री सतेन्द्र कुमार भी उपस्थित रहे। लैटिन अमेरिका क्षेत्र में इस पहले बीसी-एनईआईए से एलएसी क्षेत्र में न केवल भारत से निर्यातों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि आगे भी इस क्षेत्र में भारतीय निर्यातकों को अवसर मिलेंगे।

एक्ज़िम बैंक ने फ्लोटिंग दर वाले 5 वर्षीय फोरमोसा बॉन्ड के जरिए तिमाही लाइबोर +100 बीपीएस की दर पर जुटाए 400 मिलियन यूएस डॉलर

भारतीय निर्यात-आयात बैंक ने 7 अगस्त, 2017 को सफलतापूर्वक 5 साल के लिए रेग एस फ्लोटिंग रेट फोरमोसा बॉन्ड निर्गम जारी किया। बैंक द्वारा इस निर्गम से जुटाए गए फंड का इस्तेमाल परियोजना निर्यातों को सहयोग देने के साथ-साथ दीर्घावधि ऋण के जरिए विदेशी निवेश और ऋण-व्यवस्था पोर्टफोलियो के लिए किया जाएगा। डील की शुरुआत तिमाही लाइबोर+115 बेसिस पॉइंट की दर से हुई। अंततः बैंक तिमाही लाइबोर+100 बेसिस पॉइंट की दर पर 5 साल के लिए 400 मिलियन यूएस डॉलर का पहला रेग एस फ्लोटिंग रेट फोरमोसा बॉन्ड लाने में कामयाब रहा। यह भारत से बाहर अब तक का सबसे बड़ा फोरमोसा बॉन्ड है। साथ ही किसी भारतीय वित्तीय संस्था द्वारा पहला फोरमोसा ट्रांजैक्शन है। इस निर्गम को मौजूदा स्थायी दर बान्डो में अच्छी कीमत मिली है।

एक्ज़िम बैंक ने की ब्रिक्स आर्थिक शोध पुरस्कार 2017 के विजेता की घोषणा

डॉ. रैक्केल एल्मीडा रामोस को भारतीय निर्यात-आयात बैंक के ब्रिक्स आर्थिक शोध पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनकी डॉक्टोरल थीसिस वित्तीयकरण और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की विनिमय दरों के निर्धारण पर इसके प्रभाव' के लिए चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित 7वीं वार्षिक ब्रिक्स वित्तीय फोरम के दौरान 01 सितंबर, 2017 को प्रदान किया गया। पुरस्कार समारोह की मेजबानी चाइना डवलपमेंट बैंक (सीडीबी) द्वारा की गई। पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए (करीब 23,000 यूएस डॉलर), पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। विजेता को यह पुरस्कार चाइना डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष श्री हू हुआबैंग द्वारा प्रदान किया गया। इस दौरान ब्रिक्स के सदस्य विकास बैंकों के अध्यक्ष अर्थात ब्राजील के बीएनडीईएस के अध्यक्ष श्री पाओलो रैबेलो डी कास्त्रो; रूस के वेनेश्कोनॉम बैंक के प्रथम उपाध्यक्ष श्री निकोले शेखोम्स्की; भारतीय निर्यात-आयात बैंक के अध्यक्ष श्री डेविड रस्कीना और दक्षिण अफ्रीका के डवलपमेंट बैंक ऑफ सदर्न अफ्रीका के अध्यक्ष श्री जाबू मोलकेटी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉ. रामोस की थीसिस पर आधारित एक्ज़िम बैंक के प्रासंगिक आलेख का भी विमोचन किया गया।

संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध

भारत की पश्चिम एशिया नीति में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का बड़ा रणनीतिक महत्त्व है। भारत इसके साथ आर्थिक गतिविधियां बढ़ाते हुए खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग भी बढ़ा रहा है। दोनों मुल्कों की मेल खाती संस्कृतियां, कारोबार के अनुकूल परिवेश, निवेश की उत्सुकता और इस क्षेत्र में शांति तथा स्थायित्व बनाए रखने में इसी महत्त्वपूर्ण भूमिका व्यवसाय को सुगम बनाती हैं। व्यापार और निवेश, यूएई तथा भारत के बढ़ते आर्थिक संबंधों की आधारशिला हैं। भारत के कुल व्यापार में यूएई की अच्छी स्थिति दर्ज की गई है। जनवरी 2017 में दोनों के बीच हुए व्यापक रणनीतिक भागीदारी करार पर हस्ताक्षर के साथ दोनों मुल्कों के संबंध एक नई गति पकड़ चुके हैं।

यूएई के साथ भारत के द्विभाषिक व्यापार संबंध

भारत के साथ यूएई के व्यापक आर्थिक संबंध हैं। इन संबंधों के मूल में कहीं न कहीं दोनों देशों के अपने पारस्परिक हित जुड़े हैं। यूएई, भारत के प्रमुख व्यापार भागीदारों में से एक है। 2016 में यूएई, भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल रहा और तीसरा सबसे बड़ा आयात स्रोत रहा। हालांकि 2016 में यूएई को भारत निर्यात बढ़ा, लेकिन पिछले पांच साल से इसमें गिरावट आ रही है। 2016 में यूएई के साथ भारत का व्यापार 2011 के 72.8 अरब यूएस डॉलर से गिरकर 49.3 अरब यूएस डॉलर रह गया। इसी तरह, यूएई से भारत के आयात में भी गिरावट आई, जो 2011 के 37.4 अरब यूएस डॉलर से गिरकर 2016 में 30 अरब यूएस डॉलर रह गया।

2016 में यूएई को भारत द्वारा निर्यात की गई प्रमुख वस्तुओं में मोती, कीमती रत्न (यूएई को कुल निर्यात का 44.2%), खनिज तेल और उनके स्रावण से बने उत्पाद (12.3%), सिले हुए कपड़े और कपड़े के थान (11.7%), जहाज, नौकाएं (3.9%) और इलेक्ट्रिकल मशीनरी तथा उपकरण (2.5%) शामिल रहे।

इसी प्रकार, 2016 में यूएई से भारत द्वारा आयात की गई प्रमुख वस्तुओं में खनिज ईंधन, तेल और उनके स्रावण से बने उत्पाद (यूएई से कुल आयात का 41.9%), मोती, कीमती रत्न (40%), प्लास्टिक और प्लास्टिक की वस्तुएं (3.4%), तांबा और तांबे की वस्तुएं (2.7%) और एल्यूमीनियम तथा एल्यूमीनियम की वस्तुएं (1.7%) शामिल रहीं।

यूएई का भारत को पुनर्निर्यात

हांगकांग और सिंगापुर के बाद यूएई, विशेष रूप से दुबई विश्व का प्रमुख पुनर्निर्यात केंद्र है। इसकी भौगोलिक स्थिति और लॉजिस्टिक्स तथा परिवहन केंद्र के निरंतर विकास से यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बन गया है। यूएई की पुनर्निर्यात मजबूती इसके द्वारा की जाने वाली थोक खरीद, न्यून टैक्स, बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर पर टिकी है तथा यह व्यापारियों के लिए पुराना केंद्र भी रहा है।

यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्रालय के उद्योग एवं व्यापार सूचना विश्लेषण विभाग द्वारा प्रकाशित 2016 के अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी आंकड़ों के अनुसार, 2016 में भारत, यूएई का दूसरा सबसे बड़ा पुनर्निर्यात स्थल रहा। यूएई के पुनर्निर्यात में भारत का हिस्सा 11.4% रहा। इसके बाद ईरान का स्थान रहा, जिसका हिस्सा 14.2% रहा। यूएई द्वारा भारत को प्रमुख रूप से गैर-तेल वस्तुएं पुनर्निर्यात की गईं। इनमें हीरे (तराशे हुए अथवा सेट) गहने और आभूषण, सोना तथा अन्य कीमती धातुएं अथवा कीमती रत्न जड़ित धातुएं और इलेक्ट्रिकल कनेक्टर, इन्सुलेटर आदि रहित मशीनरी पुर्जे जैसी वस्तुएं शामिल रहीं।

यूएई के साथ भारत के निवेश संबंध

अप्रैल 2000 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान यूएई का भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आवक 4.7 अरब यूएस डॉलर रहा। संचयी एएफडीआई आवक के मामले में यूएई, भारत में 10वां सबसे बड़ा निवेशक है। भारत के कुल एफडीआई आवक में यूएई का संचयी एफडीआई 1.4% है। भारत में यूएई का निवेश मुख्य रूप से पांच क्षेत्रों पर केंद्रित है: निर्माण, बिजली, हवाई परिवहन, होटल और पर्यटन तथा धातु उद्योग। यूएई में भारतीय निवेश की बात करें तो अप्रैल 1996 से मार्च 2017 तक वहां भारत का कुल एफडीआई 15.5 अरब यूएस डॉलर का रहा।

चार्ट: यूएई के साथ भारत का व्यापार (अरब यूएस डॉलर में)

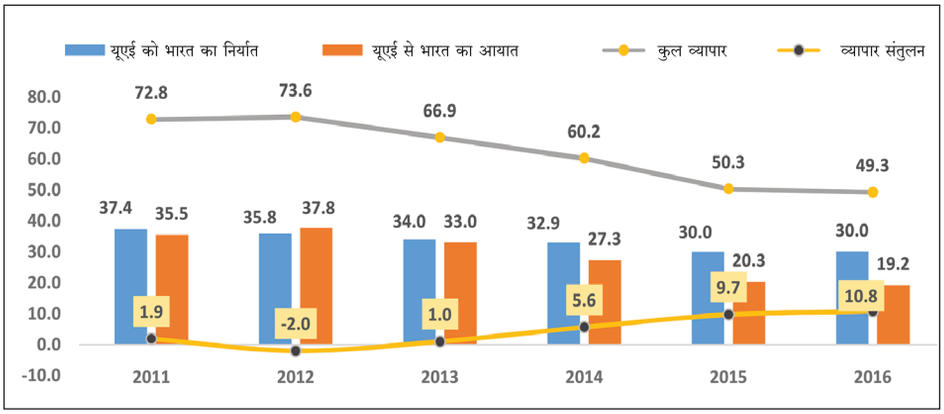

स्रोत: आईटीसी ट्रेडमैप, यूएन कॉमट्रेड

12 एक्ज़िम बैंक गतिविधियां

एक्ज़िम बैंक अपनी मार्केटिंग सलाहकारी सेवाओं के जरिए भारतीय कंपनियों की निर्यात क्षमता बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिए संवर्द्धक की भूमिका निभाता है। एक्ज़िम बैंक उन्हें विदेशों में अवसरों की तलाश करने में सहयोग करता है। इसके साथ ही भारतीय निर्यातक कंपनियों को उनके उत्पादों और सेवाओं के लिए विदेशों में वितरक/ खरीदार/ भागीदारों की तलाश में सहयोग कर उनके वैश्वीकरण प्रयासों में भी मदद करता है। बैंक कौशल विकास, उत्पाद विकास और उत्पादों को निर्यात योग्य बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर ग्रासरूट स्तर के उद्यमों का सहयोग और संवर्द्धन करता है।

बैंक ने अपने इस अनूठे कार्यक्रम के जरिए खरीदारों को चिह्नित कर तथा विदेशी बाजारों से ऑर्डर हासिल करने में सहयोग किया है। ऐसे प्रयासों को सुगम बनाते हुए बैंक ने राजस्थान के विनिर्माता और निर्यातक को ऑस्ट्रेलियाई खरीदर से लकड़ी के पैनलों के ऑर्डर हासिल करने में सहयोग किया। ऑस्ट्रेलियाई आयातक अपने स्वामित्व वाले रेस्टॉरेंट के लिए परंपरागत डिजाइन के खास पैनल चाहते थे। आयातक के ऑस्ट्रेलिया में 18 रेस्टॉरेंड हैं और उनकी योजना उन सभी में लकड़ी के नए पैनल लगवाने की है। एक्ज़िम बैंक के सहयोग से ट्रायल ऑर्डर पूरा किया गया और निर्यातक अब ऑस्ट्रेलियाई बाजार में अपनी पहुंच बढ़ा सकता है।

बैंक ने अमेरिका स्थित एक ई-कॉमर्स कंपनी से केरल के हथकरघा बुनकर सहकारी संस्थाओं को ऑर्डर दिलाने में सहयोग प्रदान किया। यह ई-कॉमर्स कंपनी नैट जियो ग्रुप का हिस्सा है, जो 2000 से ज्यादा मास्टर शिल्पियों के उत्पादों को प्रदर्शित कर रही है। एक्ज़िम बैंक के सहयोग से इन सहकारी संस्थाओं को अपने उत्पाद अमेरिका जैसे बड़े बाजारों तक प्रत्यक्ष तौर पहुंचाने और कॉर्पोरेट खरीदारों तक पहुंचने में मदद मिली। इससे उनकी निर्यात बिक्री बढ़ी और केरल के बुनकरों में एक नई तरह का आत्मविश्वास आया।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:
mas@eximbankindia.in

एक्ज़ामिअस शिक्षण केन्द्र की गतिविधियां

जुलाई-सितंबर 2017

एक्ज़ामिअस शिक्षण केन्द्र (ईसीएल) ने जुलाई-सितंबर 2017 तिमाही के दौरान निर्यातकों के लिए सात सेमिनारों का आयोजन किया। ईसीएल ने भारतीय निर्यात संघ संगठन (फिओ) के साथ मिलकर चार सेमिनारों का आयोजन किया। इनका उद्देश्य भारत सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा की गई पहलों के साथ-साथ विभिन्न कस्टम्स और प्रक्रियाओं, नीतियों तथा दस्तावेजीकरण, निर्यात-आयात संबंधी भुगतान के विषय में सूचनाओं का प्रचार-प्रसार करना है। फिओ के साथ मिलकर निम्नलिखित सेमिनार किए गए: 1. अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुगमीकरण (लुधियाना 18 जुलाई, 2017), 2. निर्यात के लिए सबसे सुरक्षित भुगतान शर्तें (भुवनेश्वर, 4 अगस्त, 2017), 3. व्यापार और निवेश वित्त पर चर्चापरक सत्र (अमृतसर, 21 अगस्त, 2017), 4. जीएसटी का कार्यान्वयन और विदेश व्यापार नीति की समीक्षा (वाराणसी, 1 सितंबर, 2017)। व्यापार कंसुलेट यूएई दूतावास, वाणिज्य एवं व्यापार तथा वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, डीजीएफटी, कस्टम्स और ईसीजीसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने उपर्युक्त सेमिनारों में हिस्सा लिया।

भारतीय लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे- परिचालन का कम अनुकूल स्तर, पुरानी पड़ चुकी प्रौद्योगिकी, अपर्याप्त आपूर्ति श्रृंखला, बढ़ती घरेलू और वैश्विक प्रतिस्पर्धा और तेजी से बदलता तथा अनिश्चत बाजार परिदृश्य। ऐसी चुनौतियों से निपटने, बड़े और वैश्विक उद्यमों से स्पर्धा करने तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने के लिए भारतीय एमएसएमई को अपने कार्यों के लिए नवोन्मेषी तरीके अपनाने और अपनी फैक्ट्रियों को स्मार्ट फैक्ट्री में बदलने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त, ज्यादातर एमएसएमई प्रमोटर के निवेश से वित्तपोषित होते हैं, जिससे उनकी वृद्धि बुरी तरह प्रभावित होती है। प्रतिस्पर्धी शर्तों पर संस्थागत वित्त की अनुपलब्धता से भी भारतीय एमएसएमई में नवोन्मेष प्रभावित होता है। ऐसे में, ईसीएल द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ मिलकर 19 जुलाई, 2017 को चंडीगढ़ में वित्तपोषण विकल्पों के जरिए एमएसएमई के विकास को बढ़ावा और उनकी स्पर्धात्मकता बढ़ाना विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया।

भावी निर्यातकों और निर्यात/आयात संबंधी गतिविधियों में संलग्न लोगों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने के उद्देश्य से एक्ज़िम बैंक इंडियन मर्चेंट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर वित्तीय वर्ष 201%-18 में महाराष्ट्र में सेमिनारों की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। ऐसा ही एक सेमिनार नवी मुंबई में 21 सितंबर, 2017 को आयोजित किया गया। इसमें फैकल्टी के रूप में डीजीएफटी, ईसीजीसी और एक्ज़िम बैंक के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

आगामी कार्यक्रम:

- मुंबई, बैंगलोर, अहमदाबाद और कोच्चि में सेवा क्षेत्र पर चर्चापरक सत्र
- विश्व बैंक निधिक परियोजनाओं में व्यवसाय अवसर (मुंबई, 13 नवंबर, 2017)
- निर्यात मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग (24 और 25 नवंबर, 2017 को भावनगर, महुआ)
- पूर्वोत्तर में विदेश व्यापार के अवसर और चुनौतियां, सिक्किम (24 नवंबर, 2017)
- अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उद्यमियों को प्रोत्साहित करना, आइजोल और इंफाल (27 नवंबर और 15 दिसंबर, 2017)
- एशियाई विकास बैंक पर सेमिनार (मुंबई, 28 नवंबर, 2017)

नेपाल

2016-17 में नेपाल ने कृषि उत्पादन और निजी खपत में वृद्धि के साथ 7.5 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। लेकिन नेपाल का कृषि क्षेत्र अगस्त 2017 के दौरान आई बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ। परिणामतः वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2017-18 में कम होकर 4.7 प्रतिशत रह गई। सरकारी अनुमानों के अनुसार, बाढ़ से 77 मिलियन यूएस डॉलर की फसल बर्बाद हुई और सिंचाई व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा। इससे आर्थिक वृद्धि भी बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है, क्योंकि नेपाल के जीडीपी में कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान है। बाढ़ के चलते व्यापार और परिवहन के प्रभावित होने से भी आर्थिक वृद्धि दर गिरने की आशंका है। इसके अतिरिक्त, रेमिटैंस आवक में गिरावट के चलते बढ़ते चालू खाता घाटे और बढ़ते आयात के कारण भी आर्थिक वृद्धि में गिरावट आने के आसार हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी कमजोर हो तथा न्यून श्रम उत्पादकता ने के चलते नेपाल द्वारा निर्यात में भी गिरावट बने रहने की आशंका है। हालांकि चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना के अंतर्गत चीन द्वारा निधिक परियोजनाओं में इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश से आगामी वर्षों में वृद्धि दर में सुधार आने की संभावना है।

नाइजीरिया

उग्रवादी गतिविधियों के चलते तेल उत्पादन में खलल पड़ने और मंदी के कारण 2016 में नाइजीरिया की वास्तविक जीडीपी में 1.6 प्रतिशत गिर गई। हालांकि नाइजीरिया अब मंदी से उबर चुका है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के चलते सुधारों की गति धीमी रहने के आसार हैं तथा राजस्व संबंधी अवरोध बुनियादी ढांचागत विकास में बाधक होंगे। तेल का निर्यात गति पकड़ सकता है और घरेलू स्तर पर मांग में कमी तथा नाइजीरिया की मुद्रा नायरा के अवमूल्यन के चलते आयात की मांग कम रहने की संभावना है। कृषि क्षेत्र में भी वृद्धि धीमी रहने की संभावना है। सूचना एवं संचार उप क्षेत्रों में बढ़त के चलते सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर के कुछ रफ्तार पकड़ने के आसार हैं। प्रौद्योगिकी तथा मनोरंजन उद्यमों के लिए नाइजीरिया क्षेत्रीय केंद्र बना रहेगा। नाइजीरियाई अर्थव्यवस्था में 2017 में 0.7 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। 2018-22 तक मल्टी-एक्सचेंज सिस्टम के बने रहने की संभावना है। आगामी वर्षों में तेल की कीमतों के औसत से कम बने रहने के चलते चालू खाता घाटा 2017 में जीडीपी का 2.3 प्रतिशत रहने के आसार हैं। आने वाले वर्षों में देश के हाइड्रोकार्बन बहुल निर्यात के विशाखन में भी बहुत अधिक प्रगति होने की संभावना नहीं है।

पेरू

वस्तुओं के मूल्य में आई गिरावट से उभरी मंदी से उबरते हुए निजी खपत और निवेश के चलते 2016 में पेरू ने 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। हालांकि अलल निनो के प्रभावस्वरूप बाढ़ के चलते 2017 में पेरू की वृद्धि दर 2.6 प्रतिशत रहने की संभावना है। पारदर्शिता और जटिल नियामकीय प्रक्रियाओं जैसे फैक्टरों से सार्वजनिक खर्च और परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित होने की आशंका है। गैस पाइपलाइन योजना गैसोडक्टो डेल सर और कस्को के पास चिंचेरो अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, ये दोनों परियोजनाएं भ्रष्टाचार के कारण रुकी पड़ी हैं। पेरू की अर्थव्यवस्था मुख्यतः इसके खनन क्षेत्र द्वारा संचालित है। हालांकि हाल के कुछ वर्षों में कृषि-उद्योग क्षेत्र में भी उत्पादकता बढ़ी है। विनिर्माण क्षेत्र में बाहरी स्पर्धा के कारण और कुशल श्रम के अभाव में वृद्धि धीमी रहने के आसार हैं। खुदरा, वित्त, पर्यटन और परिवहन में विस्तार से सेवा क्षेत्र में वृद्धि होने की संभावना है। 2018 में एफडीआई आवक द्वारा वित्तपोषित चालू खाता घाटा जीडीपी का 1.5 प्रतिशत पर स्थिर रहने की संभावना है।

चेक रिपब्लिक

उद्योग और बारही क्षेत्र चेक रिपब्लिक के लिए वृद्धि के परंपरागत इंजन के रूप में काम करते रहे हैं। वैश्विक वित्तीय संकट से पहले, पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से नजदीकी और मजबूत प्रतिस्पर्धात्मकता से एफडीआई आवक अच्छी रही और निर्यात क्षमता में भी तेजी से वृद्धि हुई। निर्यात अब जीडीपी का 80 प्रतिशत तक पहुंच गया है और चेक रिपब्लिक जर्मन-सेंट्रल सप्लाई चेन का हिस्सा है। वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2016 में 2.5 प्रतिशत रही, जो 2015 में 5.4 प्रतिशत थी, जो यूरोपीय संघ फंडिंग अवधि और नई पूंजीगत परियोजनाओं को लाने में होती देरी को प्रदर्शित करती है। निवेश में सुधार आने, घरेलू क्रय शक्ति बढ़ने और बाहरी मांग बढ़ने के चलते जीडीपी वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत रहने के आसार हैं। यूरोपीय संघ में बेरोजगारी दर के 2.9 प्रतिशत रहने से श्रम बाजार में भी गिरावट आई है और वेतन वृद्धि में भी मामूली ही बढ़त हुई है, जो निजी खपत के लिए अच्छी खबर है। इस बीच, मध्य यूरोप को यूरो जोन में हुई बढ़त, विशेष रूप से जर्मनी की अच्छी वृद्धि का लाभ मिल रहा है, जो इस क्षेत्र के ज्यादातर निर्यातों के लिए पसंदीदा स्थल है। इससे ऑटोमोटिव क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि बनी रहेगी। चेक रिपब्लिक की मुद्रा कोरुना को निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए अप्रैल 2017 तक रेगुलेट किया जा रहा था। ये नियमन हटाने के बाद मुद्रा की मूल्य वृद्धि हुई और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ गया। चालू खाता 2017 में जीडीपी के 0.9 प्रतिशत के साथ सरप्लस रहने की संभावना है।

14 मुद्रा की प्रवृत्तियां

सीएनएच (चीनी युआन)

सितंबर के पहले सप्ताह में युआन 6.5 प्रति डॉलर पर आकर रुक गया। यह एक ऐसा स्तर है, जिसे नीति निर्माताओं द्वारा लक्षित किया जा रहा था, लेकिन इसके बाद युआन और मजबूत हुआ तथा 21 महीने के उच्चतम स्तर 6.6904 पर पहुंच गया। युआन में यह मजबूती डॉलर में लगातार गिरावट, अर्थव्यवस्था के बारे में आशावादी रुख, पूंजी की जावक पर नियंत्रण और केंद्रीय बैंक द्वारा हाल ही में उठाए गए ऐसे सख्त कदमों के कारण रही, जिसके चलते युआन में 2 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी या गिरावट हो सकती थी।

युआन इस साल डॉलर के मुकाबले करीब 7.8 प्रतिशत मजबूत हुआ। इसमें मई के बाद से चुई 6 प्रतिशत की मजबूती भी शामिल है, जो 1994 के बाद से 2016 में हुई 6.5 प्रतिशत की सबसे बड़ी वार्षिक गिरावट से कहीं अधिक है।

लेकिन केंद्रीय बैंक द्वारा इस गिरावट से संभलने के लिए 2-1/2 वर्षों में व्यय किए गए 1 ट्रिलियन डॉलर, एक स्वागत योग्य कदम है, वहीं दूसरी ओर यह चिंता का विषय है कि तेजी से मजबूत होता युआन निर्यातकों के लिए अच्छा नहीं है और विस्तृत रूप में अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। अक्टूबर में कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस से पहले अर्थव्यवस्था में किसी भी तरह का खलल पड़ना ठीक नहीं होगा, जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपना और पार्टी का नेतृत्व और मजबूत करने की उम्मीद में हैं।

हालांकि इसके आसार कम ही लगते हैं कि प्राधिकारी युआन को कमजोर करने के लिए हस्तक्षेप करेंगे। क्योंकि अमेरिका द्वारा चीन पर प्रायः अपनी मुद्रा से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया जाता रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा अपने व्यापार भागीदारों की मुद्रा की प्रवृत्तियों पर एक रिपोर्ट अक्टूबर में ही जारी की जानी है। अप्रैल में इस रिपोर्ट में कहा गया था कि बीजिंग के लिए यह परीक्षा की घड़ी होग कि वे अपने मजबूत होते युआन को कैसे संभालते हैं। इससे चीन के सामने यह स्थिति पैदा हो गई थी कि अमेरिका का कोपभाजन बनने से रोकने के लिए अपने युआन को कैसे नियंत्रित करे।

बीआरएल (ब्राजीलियाई रियाल)

ब्राजीलियाई रियाल पिछले कुछ महीनों की राजनीतिक अस्थिरता के चलते (बीआरएल) मई के बाद से अगस्त में सबसे मजबूत रहा। 2 अगस्त को रियाल 3.11 प्रति यूएस डॉलर के स्तर पर बंद हुआ, जो पिछले महीने की इसी तारीख से 5.7% की मूल्यवृद्धि को दर्शाता है।

राजनीतिक घटनाक्रम, बढ़ती कमोडिटी कीमतें और अमेरिका द्वारा सख्त मौद्रिक नीति अपनाने के चलते बदलती उम्मीदों पर सवार रियाल को मजबूती मिली। राष्ट्रपति माइकल टेमर के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद निचले सदन में प्रस्ताव पारित करने पर राजनीतिक मोर्चे पर परिदृश्य इस महीने और अधिक स्थिर हो गया, ताकि डिल्मा रोसेल्फ वाली स्थिति के दोहराव से बचा जा सके। हालांकि टेमर अभी तक आरोपों से बरी नहीं हुए हैं और उन्हें भ्रष्टाचार संबंधी एक और आरोप का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन निचले सदन के इस कदम से बाजार की भावनाओं को बल मिला कि सरकार के पास सुधारों के पथ पर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक समर्थन है। इससे अंततः रियाल को मजबूती मिली। सकारात्मक राजनीतिक घटनाक्रम और यूएस फेडरल रिजर्व के अगले कदम को लेकर बदली उम्मीदों के चलते रियाल को तुलनात्मक रूप से कमजोर डॉलर का भी लाभ मिला।

हाल के घटनाक्रम के आलोक में, सितंबर के पहले सप्ताह के दौरान, रियाल बढ़कर 3.0865 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया और निकट भविष्य में इस स्तर से बहुत अधिक बढ़ने की संभावना नहीं है। इस पृष्ठभूमि में, 2017 में रियाल के 3.25-3.30 प्रति यूएस डॉलर के स्तर पर रहने की संभावना है। माना जा रहा है कि 2018 में यह 3.40 प्रति यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा।

बीडीटी (बांग्लादेशी टका)

बांग्लादेशी टका अगस्त में 80.88 प्रति यूएस डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। सितंबर के पहले सप्ताह के दौरान इसकी दर में अस्थिरता रही और यह 80.67-81.22 प्रति यूएस डॉलर के बीच रहा।

अगस्त में आई भारी बाढ़ के बाद बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ती दिखाई देती है। हालांकि कमजोर मांग एवं आपूर्ति के चलते सितंबर में निर्यात में पिछले साल इसी महीने की तुलना में 10% की गिरावट आई। इसके अतिरिक्त, बांग्लादेश के लिए विदेशी मुद्रा के एक महत्त्वपूर्ण स्रोत- रेमिटैंस भी सितंबर की बड़ी गिरावट के बाद संभला और पिछले साल के मुकाबले अक्टूबर में 14.9% बढ़ा। केंद्रीय बैंक द्वारा रेमिटैंस के गैर-कानूनी चैनलों की बेहतर निगरानी के प्रयासों से रेमिटैंस बढ़ा। 4 नवंबर को विश्व बैंक द्वारा बांग्लादेश का दौरा किया गया और म्यांमार से हजारों की संख्या में आए रोहिंग्या शरणार्थियों के आवास के लिए वित्तीय सहयोग का वादा किया गया। हालांकि इस वित्तीय सहयोग की राशि की घोषणा अभी नहीं की गई है।

आईडीआर (इंडोनेशियाई रुपैया)

सितंबर के दौरान इंडोनेशियाई रुपैया लंदन क्लोजिंग दरों पर यूएस डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 13,340.0 से 13,470.0 के स्तर पर रहा। बैंक इंडोनेशिया (बीआई) द्वारा 22 सितंबर को हुई नीतिगत बैठक में बेंचमार्क सात दिवसीय रिवर्स रेपो रेट लगातार दूसरी बार 25 बेसिस पॉइंट कम कर 4.25% कर दी गई। जमा और उधारी दरें भी 25 बेसिस पॉइंट कम कर क्रमशः 3.50% और 5.00% कर दी गई।

इंडोनेशियाई रुपैया इस साल दरों में एक और वृद्धि की उम्मीदों के चलते सितंबर में पहली बार कारोबार की तमाम ऊंचाइयां तोड़ते हुए 13,140 के स्तर पर पहुंच गया। लेकिन एफओएमसी के बाद यूएस दरों में वृद्धि की उम्मीदों के चलते यह कमजोर होकर 13,500 के स्तर पर पहुंच गया। निकट भविष्य में, डॉलर के मजबूत रहने और यूएस दरों में वृद्धि की संभावना के चलते रुपैया पर दबाव बने रहने के आसार हैं। अमेरिका-उत्तर कोरिया में तनाव बढ़ने से भी रुपैया पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, 2018 के आते-आते यूएस दरों में वृद्धि की संभावना कम होने और अन्य केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति में सख्ती के चलते रुपैया को मजबूती मिल सकती है। इस साल 22 सितंबर को बीआई द्वारा दूसरी दर कटौती के बाद, आने वाले महीनों में भी दरों में धीमी गति से कटौती की जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इसका रुपैया पर कोई बहुत अधिक असर पड़ने वाला है, क्योंकि वास्तविक यील्ड अभी साकारात्मक है। इसके अतिरिक्त, बीआई ने उम्मीद जताई है कि कि मुद्रास्फीति दर न्यून रहेगी और 2017-2019 के लिए मुद्रास्फीति दर के लक्ष्य से नीचे रहेगी। इंडोनेशिया का वास्तविक यील्ड 2.7% है, जो भारत के बाद दूसरा सबसे अधिक है। आशानुरूप, जुलाई में 0.3 अरब यूएस डॉलर का व्यापार घाटा एकबारगी ही था, जो आयात की वर्ष दर वर्ष 8.9% वृद्धि दर के मुकाबले निर्यात की 19.2% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के चलते अगस्त में वापस 1.7 अरब यूएस डॉलर के सरप्लस पर पहुंच गया।

संकेतक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
जीडीपी (वर्तमान मूल्यों पर, बिलियन यूएस डॉलर)	1823	1829	1863.2	2042.4	2073.7[f]	2230.8[f]	2448.1[f]
वास्तविक जीडीपी वृद्धि (%)	**6.7**	**5.5**	**6.4**	**7.5**	**8**	**7.1[p]**	**7.2[f]**
जीडीपी में क्षेत्रगत हिस्सा (%)							
कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	**18.5**	**17.8**	**17.5**	**16.3**	**15.3[p]**	**15.0[ae]**	-
उद्योग	32.5	31.9	31.5	31.2	31.2[p]	30.8[ae]	-
सेवाएं	49	50.3	51	52.5	53.5[p]	54.3[ae]	-
मुद्रास्फीति दर (सीपीआई, वार्षिक औसत %)	8.3	10.2	9.5	5.9	4.9	3.8	2.36 (July '17)
मुद्रास्फीति दर (डब्ल्यूपीआई, वार्षिक औसत %)	8.9	7.4	6	2	-2.5	1.7	1.88 (July '17)
सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का %)	**5.9**	**4.9**	**4.5**	**4.1**	**3.9e**	**3.5e**	**3.2[e]**
विनिमय दर (₹/यूएस डॉलर, औसत)	47.9	54.4	60.5	61.1	65.5	67.1	64.1 (Aug 24,'17)
विनिमय दर (₹/यूरो, औसत)	65.9	70.1	81.2	77.5	72.3	73.6	75.6
निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	**306**	**300.4**	**314.4**	**310.3**	**262.3**	**276.5**	**94.8 (Apr-Jul '17)**
% परिवर्तन	*22.5*	*-1.8*	*4.7*	*-1.3*	*-15.5*	*5.4*	*8.9^*
तेल निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	**56.7**	**60.9**	**63.2**	**56.7**	**30.6**	**31.6**	**8.2 (Apr-Jun '17)**
% परिवर्तन	*55.9*	*7.3*	*3.8*	*-10.2*	*-46.1*	*3.4*	*20.2^*
गैर-तेल निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	**249.2**	**239.5**	**251.2**	**253.6**	**231.7**	**244.9**	**64.0 (Apr-Jun '17)**
% परिवर्तन	*16.8*	*-3.9*	*4.9*	*0.9*	*-8.6*	*5.7*	*8.3^*
आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	**489.3**	**490.7**	**450.2**	**448**	**381**	**382.7**	**146.3 (Apr-Jul '17)**
% परिवर्तन	*32.3*	*0.3*	*-8.3*	*-0.5*	*-15*	*0.5*	*28.30^*
तेल आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	**155**	**164**	**164.8**	**138.3**	**82.9**	**86.9**	**31.0 (Apr-Jul '17)**
% परिवर्तन	*46.2*	*5.9*	*0.4*	*-16*	*-40*	*4.7*	*20.9^*
गैर-तेल आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	**334.3**	**326.7**	**285.4**	**309.7**	**298.1**	**295.9**	**115.3 (Apr-Jul '17)**
% परिवर्तन	*26.7*	*-2.3*	*-12.6*	*8.5*	*-3.8*	*-0.7*	*30.4^*
व्यापार संतुलन (बिलियन यूएस डॉलर)	**-183.3**	**-190.3**	**-135.8**	**-137.7**	**-118.7**	**-106.2**	**-51.5 (Apr-Jul '17)**
सेवा निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)* **	**140.9**	**145.7**	**151.8**	**158.1**	**154.3**	**163.1**	**39.7 (Apr-Jun '17)**
*सॉफ्टवेयर निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)*** *	62.2	65.9	69.4	73.1	74.2	73.7	-
सेवा आयात (बिलियन यूएस डॉलर)* **	**76.9**	**80.8**	**78.7**	**81.6**	**84.6**	**95.7**	**22.3 (Apr-Jun '17)**
सेवा संतुलन (बिलियन यूएस डॉलर)***	64	64.9	73.1	76.5	69.7	67.4	17.4 (Apr-Jun '17)
चालू खाता शेष (बिलियन यूएस डॉलर)	**-78.2**	**-87.8**	**-32.4**	**-26.8**	**-22.1**	**-15.2**	-
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में चालू खाता शेष (%)	*-4.2*	*-4.8*	*-1.7*	*-1.3*	*-1.1*	*-0.7*	-
विदेशी मुद्रा भंडार (बिलियन यूएस डॉलर)	**294.4**	**292**	**304.2**	**341.6**	**360.2**	**370**	**393.4 (Aug 18,'17)**
विदेशी ऋण (बिलियन यूएस डॉलर)	**360.8**	**409.4**	**446.2**	**474.7**	**485**	**471.9**	-
जीडीपी की तुलना में विदेशी ऋण अनुपात (%)	20.5	22.3	23.9	23.2	23.4	20.2	-
अल्पावधि ऋण (बिलियन यूएस डॉलर)	78.2	96.7	91.7	85.5	83.4	88	-
अल्पावधि ऋण / कुल ऋण (%)	21.7	23.6	20.5	18	17.2	18.6	-
कुल ऋण सेवा का अनुपात (%)	6	5.9	5.9	7.6	8.8	8.3	-
एफडीआई (बिलियन यूएस डॉलर)	**46.6**	**34.3**	**36**	**45.1**	**55.6**	**60**	**14.6 (Apr-Jun '17)**
जीडीआर/एडीआर (बिलियन यूएस डॉलर)	0.6	0.2	0.02	1.3	0.4	-	-
एफआईआई (नेट) (बिलियन यूएस डॉलर)	16.8	27.6	5	40.9	-4	7.7	11.9 (Apr-Jun '17)
एफडीआई जावक (बिलियन यूएस डॉलर)	**10.9**	**7.1**	**9.2**	**4**	**8.9**	**7**	**2.8 (Apr-Jun '17)**

स्रोतः आर्थिक सर्वेक्षण, विभिन्न अंक; केन्द्रीय बजट, आर बी आई मासिक बुलेटिन, वार्षिक रिपोर्ट और साप्ताहिक सांख्यिकीय सप्ली; वित्त मंत्रालय; सी एस ओ; ईआईयू; नैसकॉम, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान (आई आई एफ), डब्ल्यू ई ओ, आई एम एफ.

नोटः भारत सरकार के अनुमान; पी- ई ए सी, भारत सरकार के अस्थाई अनुमान; एफ - आई आई एफ अनुमान; -उपलब्ध नहीं; -आई आई एफ अनुमान; -% गत वर्ष की तुलना में वर्तमान अवधि में परिवर्तन; - उपलब्ध नहीं; ** संशोधित आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार डेटा; - पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान वृद्धि

व्यापार और भागीदारी अवसर

व्यापार अवसर

कृषि कमोडिटी

विनिर्माण और व्यापार कंपनी तरबूज, खरबूज और कद्दू के बीज, खोपरा, मूंगफली के दाने विभिन्न प्रकार की पैकेजिंग में उपलब्ध कराती है। यह कंपनी दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका तथा मध्य पूर्व के देशों को निर्यात करती है।

कृषि उपकरण

आईएसओ प्रमाणित कंपनी खेती में काम आने वाले ट्रैक्टर, क्रेन, इंजन और डीजल जेनरेटर जैसे उपकरणों का विनिर्माण करती है। 1994 में स्थापित इस कंपनी को विभिन्न कृषि उपकरणों के विनिर्माण और निर्यात में दो दशक से भी ज्यादा का अनुभव है।

स्टेनलेस स्टील के बर्तन

स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाने वाली अग्रणी कंपनियों में से एक यह कंपनी होटल वेयर, टेबल वेयर और अन्य कैटरिंग उत्पाद बनाती है। कंपनी के बर्तन विभिन्न डिजाइनों और आकारों में उपलब्ध हैं।

घरेलू टेक्सटाइल और एसेसरीज

गुजरात का एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) इस क्षेत्र की 1600 से अधिक जनजातीय महिलाओं के साथ मिलकर काम करता है। यह एनजीओ गुजरात के जनजातीय समुदाय के चहुंमुखी और उद्यमशील विकास में प्रयासरत है। इन दस्तकारों द्वारा बनाए गए उत्पादों में घरेलू टेक्सटाइल और विभिन्न एसेसरीज शामिल हैं। ये सभी उत्पाद क्राफ्टमार्क द्वारा प्रमाणित और मान्यता प्राप्त हैं।

उपयोग और घरेलू साज-सज्जा के उत्पाद

1990 में स्थापित एक विकासशील संगठन, जिसकी स्थापना प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं के संघ के रूप में हुई थी। यह ओडिशा में उद्यमिता को बढ़ावा देने का काम करता है। इसके उत्पाद ढोकरा शिल्प के इस्तेमाल से बनाए जाते हैं, जिनमें जनजातीय गहने, विमान, कलाकृतियां और ऑफिस स्टेशनरी शामिल हैं।

एटिकोप्पाका वुडन लैकेवेयर

यह कला शिल्प आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव एटिकोप्पाका से आती है, जो अब लगभग लुप्त होने की कगार पर है। ये लैकेवेयर उत्पाद लकड़ी के बने होते हैं और विभिन्न बीजों, पेड़ों की छालों, जड़ों और पत्तियों से बने प्राकृतिक रंगों से इन्हें पेंट किया जाता है।

सहभागिता अवसर

परियोजना अवसर

(I) दक्षिण अफ्रीका में जल परियोजना द्वितीय चरण में है। इसमें एक बांध और सुरंग का निर्माण तथा जलविद्युत उत्पन्न करने संबंधी कार्य शामिल हैं। यह बहु चरणीय परियोजना है, जिसके जरिए दक्षिण अफ्रीका के ग्वातेंग क्षेत्र में जल आपूर्ति की जाती है और लेसोथो के लिए जलविद्युत उत्पन्न करने के लिए जल आपूर्ति व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाता है।

निर्यात अवसर

(I) एक कैरिबियाई आयातक रसायनों के आयात का इच्छुक है। फॉर्मैल्डहाइड गैस, कास्टिक सोडा, लीनियर सल्फोनिक एसिड, प्रोपीलीन, ग्लाइकोल और एक्वीअस अमोनिया सॉल्यूशन। भारतीय निर्यातकों से सी एंड एफ कॉसीडो अथवा रियो हाइना पोर्ट, डोमिनिक रिपब्लिक में कोट आमंत्रित हैं।

(II) म्यांमार से एक आयातक कृषि कार्यों के लिए यूरिया का आयात करने का इच्छुक है। कंपनी को प्रत्येक माह 3000 मीट्रिक टन उर्वरक की आवश्यकता है।

(III) म्यांमार की ही एक और आयातक कंपनी मार्केटिंग सलाहकारी समूह से संपर्क करना चाहती है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

इच्छुक पार्टियां मार्केटिंग सलाहकारी सेवाएं समूह से नीचे दिए पते पर संपर्क कर सकती हैं।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया कॉल करें - फ़ोन: 2217 2600, विस्तार: 2707/2737, फ़ैक्स: 2218 8268, ई-मेल: **mas@eximbankindia.in**